संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज | समूह संपादक : रवि भारद्वाज | ऊना, मंगलवार 31 मार्च 2026 ₹ 2 | www.actionindialive.com | Facebook.com/actionindialivee

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
एक्शन इंडिया

वर्ष: 15 अंक: 90 पृष्ठ: 08 | RNI : HPHIN/2012/48072
actionindiauna@gmail.com | हिमाचल संस्करण | दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड - चंडीगढ़

RKB GROUP
Rakesh Bhardwaj Group

देश में बैंक एक सख्त कानूनी और नियामक ढांचे के तहत काम करते हैं: सीतारमण।

देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता: केंद्र

सरकार ने देशवासियों और उद्योग जगत को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रहने का भरोसा दिया

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली/दीपचंद्र काण्डपाल
पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच सरकार ने देशवासियों और उद्योग जगत को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रहने का भरोसा दिया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक हालात के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। हालांकि, कुछ जगहों पर ग्राहकों के घबराहट में की जा रही खरीदारी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने देश के ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए कई स्तरों पर त्वरित उपाय किए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोमवार को अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दुनियाभर के अलग-अलग देशों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में 28 मार्च को प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र में ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए हमलों की निंदा की। दोनों नेताओं ने स्वतंत्र आवागमन और शिपिंग मार्गों को खुला और सुरक्षित रखने पर भी चर्चा की। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और तेल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तरों पर कदम उठाए हैं और उठाती रहेगी। हमारी रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का स्टॉक भी पर्याप्त है। इसके अलावा घरेलू बाजार में डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की उपलब्धता बनाए रखने के लिए एक निर्यात शुल्क भी लगाई गई है। सुजाता शर्मा ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं और सीएनजी आधारित परिवहन के लिए 100 फीसदी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक की कोई कमी नही

ग्रिड से जुड़ी इंडस्ट्रीज के लिए 80 फीसदी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। एलपीजी के संबंध में उन्होंने कहा कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। शर्मा ने बताया कि लगभग 95 फीसदी बुकिंग ऑनलाइन की गईं। पिछले एक हफ्ते में लगभग 2,60,005 किलोग्राम एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलेंडर बेचे गए हैं। साथ ही लगभग 41,000 टन कमर्शियल एलपीजी भी उठाई गई है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नियमित तिमाही आवंटन के अलावा अतिरिक्त 48 हजार किलोलीटर केरोसिन आवंटित किया गया है।

विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश का औद्योगिक उत्पादन फरवरी महीने में 5.2 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली। देश का औद्योगिक उत्पादन विनिर्माण क्षेत्र में सुधार से फरवरी में 5.2 फीसदी बढ़ा है, जो एक मजबूत सुधार को दर्शाता है। पिछले साल फरवरी 2025 में यह वृद्धि केवल 2.7 फीसदी रही थी।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) पर आधारित देश का औद्योगिक उत्पादन फरवरी में विनिर्माण क्षेत्र में सुधार से फरवरी में 5.2 फीसदी बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार फरवरी में विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि तेज होकर छह फीसदी हो गई, जबकि एक वर्ष पहले इसी महीने में यह 2.8 फीसदी थी। मंत्रालय के मुताबिक फरवरी में खनन क्षेत्र की वृद्धि भी

थोड़ा सुधरकर 3.1 फीसदी हो गई, जबकि फरवरी, 2025 में यह 1.6 फीसदी थी। बिजली उत्पादन फरवरी में 2.3 फीसदी बढ़ा है, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह 3.6 फीसदी बढ़ा था। मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल से फरवरी अवधि के दौरान देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 4.1 फीसदी पर स्थिर रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के बराबर है।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कवींद्र गुप्ता ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

केवल संघ को ही विदेशी फंड मिलेगा, संघ नफरत फैलाता है: राहुल गांधी

टीम एक्शन इंडिया
कोट्टायमः देश के 5 राज्यों में अप्रैल में चुनाव हैं। सभी राज्यों में पार्टियों की जनसभा, रैली और प्रत्याशियों का जनसंपर्क जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज केरल दौरे पर हैं। उन्होंने कोट्टायम में कहा- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम में संशोधन विधेयक लाया जाना है। जिससे गंभीर बात है, क्योंकि इसके तहत केवल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ही विदेशी फंड प्राप्त कर सकेगा, जबकि अन्य संगठनों पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संघ में ऐसी क्या खास बात है कि उनके लिए अलग नियम हैं? वे नफरत फैलाते हैं

और लोगों को बांटते हैं। भाजपा इसी तरह काम करती है। इससे पहले पतनमतिट्टा में राहुल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प के दबाव में हैं। ठीक इसी तरह, नरेंद्र मोदी आपके मुख्यमंत्री को भी अपने इशारों पर नचाते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बेल्दा में चुनावी सभा में कहा- भाजपा समाज के सभी वर्गों के बीच झगड़ा भड़का रही है। चुनाव के बाद गैस और कैश देना बंद कर देगी। भाजपा देश लूटना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में बीजेपी कार्यकर्ताअें से नमो एप के जरिए ऑनलाइन चर्चा की। वहीं केरल में घर से वोटिंग शुरू प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो लोग वोट डालने जाने में असमर्थ हैं, उनसे पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कराई जा रही है।
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सोमवार को चेन्नई के कोलाथुर सीट से नामांकन दाखिल किया। टीवीके चीफ विजय ने पेरम्बूर सीट से नामांकन दाखिल किया।

पात्रा ने कांग्रेस पर लगाया, नक्सलवाद को पालने पोसने का आरोप

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद डॉ. संबित पात्रा ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के शासनकाल में अगर कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा द्वारा शुरू किये गये सलवा जुडूम जैसे आंदोलन को रोका ना गया होता तो भारत 2020 के पहले ही नक्सल मुक्त हो जाता। लोकसभा में नक्सलवाद-मुक्त भारत विषय पर नियम 193 के तहत हुई अल्पकालिक चर्चा में भाग लेते हुए

डॉ पात्रा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की सबसे घातक समस्या बताया था, लेकिन कांग्रेस के दूसरे धड़े ने इसे रोमांचकारी गतिविधि के रूप में दिखाने का काम किया। इसी का परिणाम था कि कांग्रेस के एक आदिवासी नेता ने नक्सलियों के खिलाफ 2005 में सलवा जुडूम आंदोलन शुरू किया।

वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए जगह तलाशी जाएं: सीएम

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्लीः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा भर में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं जाने के लिए स्थान ढूंढने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान कई स्थानों पर जलभराव की समस्या सामने आती है, इसलिए इससे निपटने के लिए अभी से पुख्ता इंतजाम किए जाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को सचिवालय में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने बारिश से पहले होने वाली ड्रेन को सफाई, जल निकासी व्यवस्था और सफाई व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की

तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि जहां-जहां जल निकासी में दिक्कत है, उन स्थानों की पहचान कर वहां वैकल्पिक उपाय अपनाए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि ऐसे स्थानों पर वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के विकल्प तलाशे जाएं, ताकि वर्षा जल का संचयन हो सके और जलभराव की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में वॉटर हार्वेस्टिंग से जुड़ा पूरा और अपडेटेड डेटा तैयार किया जाए। इसमें यह जानकारी शामिल हो कि कहां-कहां वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

> ☐ कई स्थानों पर जलभराव की समस्या सामने आती है, इसलिए इससे निपटने के लिए अभी से पुख्ता इंतजाम किए जाए

लगे हुए हैं, उनमें से कितने सही तरीके से काम कर रहे हैं और किन स्थानों पर इन्हें लगाने की आवश्यकता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विभागों में इन सिस्टम्स को सही तरीके से लागू किया जाए और जहां यह अभी तक नहीं लगे हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर इन्हें स्थापित किया। जाए। उन्होंने यह भी कहा कि

प्रधानमंत्री का असम के भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को असम के भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के माध्यम से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा-एनडीए की हैट्रिक जीत के लिए कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने की अपील की। उन्होंने विपक्षी दलों पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा असम की अस्मिता, सुरक्षा और संस्कृति से सीधे जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को नमो ऐप के जरिए 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' कार्यक्रम के तहत राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी दायित्व सौंपती है, उसे निभाने के लिए वे पूरी ताकत लगाते हैं। असम में भाजपा-एनडीए की हैट्रिक लगे, इसके लिए राज्य के पार्टी कार्यकर्ता जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोहाग बिहू और अन्य त्योहारों की तैयारियों के बीच चुनावी अभियान चलाने वाले कार्यकर्ताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि असम ने लंबे समय तक अस्थिरता, हिंसा और उग्रवाद का दौर देखा था,

लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार ने शांति, विकास और सुरक्षा का नया दौर शुरू किया है। पिछले 10 वर्षों में 12 बड़े शांति समझौते हुए हैं जो असम की नई तस्वीर बनाते हैं। संवाद के दौरान विभिन्न जिलों के कार्यकताओं ने अपने अनुभव साझा किए। सुनितपुर जिले के पंकज हजारी ने कहा कि साल 2016 से पहले असम में अराजकता और उग्रवाद चरम पर था। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद किसानों, व्यवसायियों और शिक्षकों के जीवन में अमूल्य परिवर्तन आया है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 18-22 साल के युवा मतदाता केवल पिछले 10 साल की शांति को जानते हैं, बूथ कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि उन्हें पुराने दिनों की हिंसा और कांग्रेस की नीतियों की याद दिलाएं।

जायका सहयोग से मेडिकल शिक्षा व स्वास्थ्य ढांचे पर 3 हजार करोड़ खर्च: सीएम सुक्खू

पंकज शर्मा
शिमला। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कटौती प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में जायका के माध्यम से लगभग तीन हजार करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इस राशि से कॉलेजों में अत्याधुनिक उपकरण स्थापित किए जाएंगे, जिससे मरीजों को उच्च स्तर की उपचार सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की सेवाओं में लगातार सुधार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेज–चंबा, नाहन, हमीरपुर और नेरचौक–में विशेष सुधार की आवश्यकता है और आगामी एक वर्ष में इन संस्थानों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय के लिए राज्य के पास धन की कमी नहीं है, हालांकि वेतन और पेंशन का व्यय अधिक होने के कारण दबाव रहता है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि रोबोटिक सर्जरी के लिए 'द विंची' मशीन 24 करोड़ रुपये में खरीदी गई है। यह मशीन एम्स द्वारा खरीदी गई मशीन की तुलना में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपये कम लागत पर प्राप्त की गई है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च के बाद मशीन नए दरों पर उपलब्ध होगी, जिसके बाद पुनः निविदा प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 'द विंचीइ विश्व स्तरीय रोबोटिक सर्जरी मशीन है और इसकी खरीद पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि पैट स्कैन मशीनें भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई हैं। रोबोटिक सर्जरी मशीन, एमआरआई और पैट स्कैन उपकरणों की खरीद निविदा प्रणाली से की गई है।

कृषि अवशेष से बनेंगी सड़कें, सीएसआईआर ने बायो-बिटुमेन तकनीक का किया हस्तांतरण

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली। बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने सोमवार को अपनी अभिनव तकनीक लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास से बायो-बिटुमेन खेतों के अवशेष से सड़कों तक के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपयोग के लिए तकनीक का हस्तांतरण किया। सीएसआईआर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं

किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह, सीएसआईआर की महानिदेशक एन. कलाईसेल्वी तथा विभिन्न मंत्रालयों, सीएसआईआर संस्थानों, उद्योग और नीति-निमार्ताओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने बायो-बिटुमेन तकनीक को ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताते हुए कहा कि यह तकनीक कृषि को बुनियादी ढांचे और नवाचार को जोड़ता है। यह तकनीक भारत के जलवायु लक्ष्यों, नेट जीरो प्रतिबद्धताओं, आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय बायो-ऊर्जा मिशन और सर्कुलर इकोनॉमी जैसी पहलों के अनुरूप है। इसके उपयोग से किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह पहल भारत की आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और वेस्ट टू वेल्थ की सोच को दशार्ती है। यह तकनीक कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों के बीच प्रभावी समन्वय का उदाहरण है।

> ☐ केवल इसलिए कि योजना के आगे प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है, टीएमसी सरकार इसे लागू नहीं कर रही: शिवराज

केरल, असम और पुडुचेरी के 2.37 लाख दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाता करेंगे घर से ही मतदान

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली। चुनाव आयोग 85 वर्ष से अधिक आयु और द्विव्यांग मतदाताओं को घर से मतपत्रों के जरिए मतदान की सुविधा प्रदान करता है। केरल, असम और पुडुचेरी में अबतक 2.37 लाख पात्र मतदाताओं ने इस सुविधा के लिए आवेदन दिया है। इन राज्यों में 9 अप्रैल को मतदान है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि केरल में 1.45 लाख, असम में 19 हजार और पुडुचेरी में दो हजार से अधिक वरिष्ठ एवं द्विव्यांग मतदाओं ने इस सुविधा के लिए आवेदन किया है। आवेदन करने वालों में 1.67 लाख वरिष्ठ नागरिक (53.5 प्रतिशत) एवं 70 हजार से अधिक द्विव्यांग मतदाता (15.22 प्रतिशत) हैं। इन सभी को आयोग की ओर से जानकारी दी जाएगी की कब मतदान कर्मी राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ उनके घर मतदान के लिए आएंगे। यह प्रक्रिया 5 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। आयोग की ओर से पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है।

इससे छोटी गाड़ियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, जबकि बड़ी गाड़ियों पर करीब 40 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है: मुख्यमंत्री

एंट्री टैक्स नया नहीं, सिर्फ बढ़ोतरी हुई, सरकार करेगी रैशनलाइजेशन: सुक्खू

> ☐ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने कोई नया एंट्री टैक्स लागू नहीं किया है

टीम एक्शन इंडिया
पंकज शर्मा
शिमला। पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ एंट्री टैक्स को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने कोई नया एंट्री टैक्स

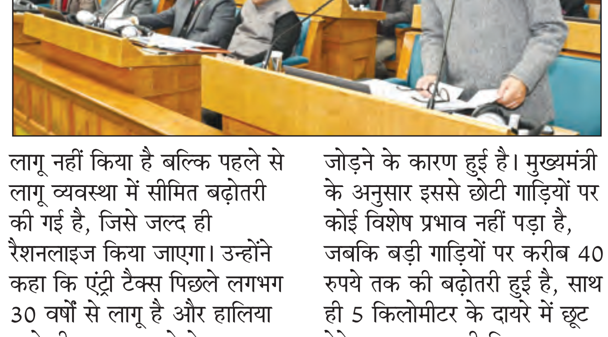

लागू नहीं किया है बल्कि पहले से लागू व्यवस्था में सीमित बढ़ोतरी की गई है, जिसे जल्द ही रैशनलाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स पिछले लगभग 30 वर्षों से लागू है और हालिया बढ़ोतरी मुख्य रूप से नेशनल हाईवे पर फास्टैग प्रणाली से इसे जोड़ने के कारण हुई है। मुख्यमंत्री के अनुसार इससे छोटी गाड़ियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, जबकि बड़ी गाड़ियों पर करीब 40 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, साथ ही 5 किलोमीटर के दायरे में छूट देने का प्रावधान भी किया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। इससे पहले, प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इस फैसले के कारण पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ तनाव की स्थिति बन रही है और वहां के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिससे दोनों राज्यों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और हिमाचल के लोगों को दूसरे राज्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार से बातचीत कर समाधान निकालें, क्योंकि इसका व्यापक असर टैक्सी यूनियनों और आम लोगों पर पड़ रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने भी चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को रैशनलाइजेशन से पहले ठेकेदारों और संबंधित पक्षों को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सीमा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कुछ स्थानों पर सीमा बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने दोहराया कि एंट्री टैक्स कोई नई व्यवस्था नहीं है और इसका असर छोटी गाड़ियों पर नहीं पड़ेगा।

उत्तर भारत

ACTION INDIA

ऊना, 31 मार्च 2026

दैनिक एक्शन इंडिया

www.actionindialive.com

एशियाई खेलों के चयन पर नजर, कोमालिका दमदार प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त

☐ कोमालिका विश्व कैडेट और विश्व जूनियर खिताब जीतने वाली भारत की दूसरी महिला रिकर्व तीरंदाज हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बेटी को तीरंदाजी अपनाने के लिए किया प्रेरित, कोमालिका का मानना है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से जनजातीय क्षेत्रों से कई प्रतिभाएं आ सकती हैं सामने, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्सः महिला हॉकी में मिजोरम और ओडिशा पहुँचे फाइनल में

परियोजना

☐ प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में पहले चरण का करीब 95 प्रतिशत निर्माण कार्य संपन्न हो गया

टीम एक्शन इंडिया

रायपुरः साल 2021 में जब कोमालिका बारी ने अपनी राज्य की साथी दीपिका कुमारी की बराबरी करते हुए विश्व कैडेट और विश्व जूनियर दोनों खिताब जीतने वाली भारत की दूसरी महिला रिकर्व तीरंदाज बनने का गौरव हासिल किया, तब जमशेदपुर की इस खिलाड़ी से काफी सारी उम्मीदें जुड़ गई थीं। हालांकि, जूनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद सीनियर सर्किट में उनका सफर उतना आसान नहीं रहा। कोमालिका एशियाई खेलों और 2028 ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट्स के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक वह पूरी तरह अपनी जगह पक्की नहीं कर पाई हैं। अब 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में चयन की दौड़ अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, ऐसे में कोमालिका ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। पुणे में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में वह अपनी तकनीक को निखारने के साथ-साथ मानसिक मजबूती और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने पर भी खास ध्यान दे रही हैं। कोमालिका ने साई मीडिया को कहा कि, मैं फिलहाल टॉप-16 में हूं और राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा हूं। एशियाई खेलों के चयन को लेकर मैं गंभीरता से तैयारी कर रही हूं। साथ ही, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अनुभव हासिल करना चाहती हूं, जबकि अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी बनाए रख रही हूं। झारखंड की यह प्रतिभाशाली तीरंदाज यहां जारी पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में तीरंदाजी प्रतियोगिता की प्रमुख आकर्षण हैं। कोमालिका ने आगे कहा कि, मेरा अंतिम लक्ष्य (2028) ओलंपिक है। इस समय मेरा प्रशिक्षण काफी अच्छा चल रहा है और मैं कड़ी मेहनत कर रही हूं। सबसे ज्यादा ध्यान मानसिक रूप से मजबूत रहने पर है, क्योंकि प्रदर्शन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, मेरी यात्रा ने मुझे सिखाया है कि उतार- चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से उन्हें पार कर आगे बढ़ा जा सकता है।

कोमालिका ने 12 साल की उम्र में पहली बार धनुष-बाण उठाया

मैच अनुभव हासिल करने के अलावा वह अधिक से अधिक जनजातीय बच्चों को इस खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। कोमालिका ने 12 साल की उम्र में पहली बार धनुष-बाण उठाया। उन्हें उनकी मां, जो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, का पूरा समर्थन मिला। उनकी मां ही उन्हें बिरसानगर में स्थानीय तीरंदाजी कोच के पास लेकर गईं, जहां से उनके करियर की शुरूआत हुई। साल 2012 में कोमालिका ने अपने शुरूआती संघर्षों का सामना करना शुरू किया। शुरूआती दिनों में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे अभ्यास के लिए धनुष खरीद सकें, इसलिए उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान बांस से बने अस्थायी धनुष का सहारा लिया। प्रशिक्षण शुरू करने के चार साल बाद कोमालिका ने जमशेदपुर स्थित टाटा आर्चरी अकादमी में प्रवेश लिया और कोच धर्मेंद्र तिवारी तथा पूर्णिमा महतो के मार्गदर्शन में अभ्यास शुरू किया। लेकिन देश की इस प्रतिष्ठित अकादमी तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने बिरसानगर स्थित घर से रोजाना 18 किलोमीटर साइकिल चलाकर वहां पहुंचना पड़ता था।

वह कहती हैं, जब मैंने तीरंदाजी शुरू की थी, तब मेरे कई सीनियर खिलाड़ी थे जिन्हें मैं रोल मॉडल मानती थी। हमें उन्हें आमतौर पर सिर्फ प्रतियोगिताओं के दौरान देखने का मौका मिलता था और इससे हमें काफी प्रेरणा मिलती थी। उन्होंने आगे कहा कि, यही एक बड़ा कारण है कि मैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में हिस्सा ले रही हूं। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे खेलते हुए देखें और आगे आकर भाग लेने के लिए प्रेरित हों। अभी भी कई लोग भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स एक बहुत अच्छा मंच है, जो प्रेरणा और अवसर दोनों प्रदान करता है।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्सः महिला हॉकी में मिजोरम और ओडिशा पहुँचे फाइनल में

रायपुर। 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026' के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले आज सोमवार को उत्साह और रोमांच के बीच खेले गए। पहले सेमीफाइनल मैच में मिजोरम की टीम ने झारखंड को कड़े मुकाबले में 3-2 से पराजित कर फाइनल में स्थान बनाया। दोनों टीमों के बीच मैच बेहद प्रतिस्पर्धात्मक रहा, जिसमें मिजोरम ने अंत तक बढ़त बनाए रखी। दूसरे सेमीफाइनल मैच में उड़ीसा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश को 8-0 से हराया। उड़ीसा की टीम ने पूरे मैच में आक्रामक खेल दिखाते हुए एकतरफा जीत दर्ज की। इन परिणामों के साथ मिजोरम और उड़ीसा की टीमें अब फाइनल में आमने-सामने होंगी, जहाँ खेल प्रेमियों को खिताब के लिए रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026: पुरुष भारोत्तोलन 88 किग्रा वर्ग में अरुणाचल के रुबा ताडु बने चैंपियन

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 प्रतियोगिता में 88 किलोग्राम वर्ग पुरुष भारोत्तोलन में अरुणाचल प्रदेश के रुबा ताडु ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कुल 274 किलोग्राम वजन उठाकर पहला स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रुबा ताडु ने स्नैच में 117 किग्रा तथा क्लीन एंड जर्क में 157 किग्रा वजन उठाकर शीर्ष स्थान सुनिश्चित किया।

बिहार में बिजली दरों पर सियासत तेज, तेजस्वी का वादाखिलाफी का आरोप

साधा निशाना

☐ नीतीश-भाजपा फिर पलटी मार गई और जनता से अधिक बिजली शुल्क वसूलने की तैयारी कर रही हैः तेजस्वी

टीम एक्शन इंडिया

पटना। बिहार में 1 अप्रैल से बिजली दरों में संभावित बड़े बदलाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर तीखा हमला बोला है और चुनावी वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली सरकार अब महज चार महीने में ही अपने वादे से पलट गई है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश-भाजपा फिर पलटी मार गई और जनता से अधिक बिजली शुल्क वसूलने की तैयारी कर रही है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने दावा किया कि नई प्रस्तावित दरों के अनुसार शाम 11 बजे तक के सर्वाधिक खपत वाले 6 घंटों के लिए 8.10 रुपये प्रति यूनिट, रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक के 10 घंटों के लिए 7.10 रुपये प्रति यूनिट और शेष 8 घंटों के लिए 5.94 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल लिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 हजारिया के फेर में फौरी तौर पर खुश होकर वोट गिरवी रखने वालों को यह सरकार अभी इससे भी बुरे दिन दिखाएगी। नई सरकार के अभी 4 महीने ही हुए है, सरकार का खजाना एकदम खाली है और जो बचा-खुचा है उसे भ्रष्ट अधिकारी स्वयं समेट लेंगे।

लोकसभा में फिर उठाई सांसद हेमा ने ब्रज के समग्र विकास की आवाज

टीम एक्शन इंडिया

मथुरा। लोकसभा में मथुरा ब्रज के समग्र विकास को लेकर भाजपा सांसद हेमामालिनी ने शनिवार जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने ब्रज क्षेत्र को एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की। अपने सम्बोधन की शुरूआत सांसद ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा उनके नेतृत्व में मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हुए हैं। सांसद ने कहा, आज मथुरा को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिल रही है। जिससे देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से वृन्दावन में बढ़ती भीड़ का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में ही यहां भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद यह संख्या और तेजी से बढ़ेगी।

विशेष पैकेज

☐ साफ-सफाई और सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने की मांग की, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके

पर्यटन विकास के मुद्दे पर बोलते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि मथुरा और वृंदावन के घाटों व मंदिरों के आसपास आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने घाटों के सौंदर्यीकरण, साफ-सफाई और सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने की मांग की, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा

टीम एक्शन इंडिया

पटना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वह विधानसभा में पटना के बांकीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया, "बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन एवं कार्यकर्ता साथी, जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरूआत की। पिछले 20 वर्षों में पिताजी, स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा द्वारा बनाए गए इस क्षेत्र को पारिवारिक भाव से सींचने, संवारने और विकास के पटल पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास किया है।" उन्होंने लिखा, "मैंने सदैव अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य किया । इसी का प्रतिफल है कि यहां की देवतुल्य जनता ने मुझे लगातार पांच बार सदन में अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, दोनों ही स्थानों का उपयोग मैंने अपने क्षेत्र और बिहार की जनता की आवाज उठाने और उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने के लिए किया।

भावुक हुए

☐ मैंने सदैव अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कियाः नवीन

बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ विधायकों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। मैंने अपने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विषयों का समाधान जनता और कार्यकर्ताओं के सुझावों से ही निकाला है।" नवीन ने लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार्टी ने जब मुझे बिहार सरकार के मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया।

सपा और पीडीए मिलकर 2027 में बनाएगी सरकार, घबराई हुई है भाजपाः शिवपाल

टीम एक्शन इंडिया

कानपुर। सपा और पीडीए मिलकर 2027 में सरकार बनाएंगे, जिसे लेकर भाजपा पूरी तरह घबराई हुई है। भाजपा केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और प्रदेश व देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा ने अब तक सिर्फ लूट का काम किया है, जिसका जवाब जनता आगामी चुनाव में देगी। यह बातें शनिवार को होली-ईद मिलन समारोह में पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहीं।

कानपुर के चुन्नीगंज स्थित जीआईसी ग्राउंड में सपा विधायक नसीम सोलंकी द्वारा होली-ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और जौनपुर की मछलीशहर सीट से विधायक डॉ. रागिनी सोनकर शामिल रहीं। इस दौरान विधायक नसीम सोलंकी ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया।

पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि यदि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है तो जनता को लाइनों में क्यों लगना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एलपीजी गैस समय पर उपलब्ध कराई जा रही है।

तो गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें क्यों दिखाई दे रही हैं।

ग्रेटर नोएडा में सजेगा कौशल का महाकुंभ

टीम एक्शन इंडिया

नोएडा। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीए) द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तत्वावधान में आयोजित होने वाली देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता, 'इंडियास्किल्स नेशनल कॉम्पिटिशन 2025-26', का भव्य आयोजन रविवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में होगा। उत्तर प्रदेश में इस बड़े आयोजन को सफल बनाने में योगी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार प्रदेश को स्किल डेवलपमेंट का हब बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है और इस तरह के आयोजनों से युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है।

यह द्विवार्षिक प्रतियोगिता देश के प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी दक्षता प्रदर्शित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पधाओं के लिए तैयार करने का एक अद्वितीय मंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले असम, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की रीजनल प्रतियोगिता हो चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 40 प्रतिभागियों ने हुनर दिखाया था। इनमें से 16 प्रतिभागियों ने अलग-अलग मेडल अपने नाम किए थे।

एक्सपो मार्ट

☐ प्रतियोगिता 30 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक इंडिया एक्सपो मार्ट के हॉल 9 से 12 में आयोजित होगी

इंडियास्किल्स नेशनल कॉम्पिटिशन 2025-26 के अंतर्गत उद्घाटन समारोह 29 मार्च 2026 को दोपहर 3 से 5 बजे तक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद प्रतियोगिता 30 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक इंडिया एक्सपो मार्ट के हॉल 9 से 12 में आयोजित होगी।

आधुनिक तकनीक के साथ संवेदनशीलता ही नई पुलिसिंग की पहचानः मुख्यमंत्री साय

टीम एक्शन इंडिया

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में आयोजित उप निरीक्षक संवर्ग के दीक्षांत (पासिंग आउट परेड) समारोह में शामिल हुए। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस अवसर पर सूबेदार, उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर संवर्ग के अधिकारियों को सफल प्रशिक्षण पूर्ण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस सत्र में कुल 859 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूर्ण किया, जिनमें 54 सूबेदार, 528 उप निरीक्षक (जीडी), 02 उप निरीक्षक (कंप्यूटर), 01 उप निरीक्षक (रेडियो), 01 उप निरीक्षक (अंगुली चिन्ह), 68 उप निरीक्षक (एसबी) तथा 205 प्लाटून कमांडर शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि यह दिन सभी प्रशिक्षुओं के जीवन का एक यादगार पड़ाव है, जहाँ से वे राष्ट्र और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कठोर प्रशिक्षण के बाद प्राप्त यह उपलब्धि न केवल प्रशिक्षुओं के लिए, बल्कि उनके परिजनों और पूरे प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है। उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले वर्ष जब उन्होंने इन्हीं युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे, तब उनके पास प्रतिभा थी, और आज प्रशिक्षण के बाद उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का समावेश हो चुका है, जो उन्हें एक सफल अधिकारी बनाएगा। मुख्यमंत्री साय ने पुलिस सेवा को अत्यंत प्रतिष्ठित एवं जिम्मेदारीपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी भी प्रतिष्ठित सेवा का आधार सत्यनिष्ठा होती है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को प्रेरित करते हुए कहा कि पुलिस का मूल दायित्व नागरिकों की रक्षा करना है।

सुरक्षा का संकल्प

☐ वर्दी केवल अधिकार नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा का संकल्प और उससे जुड़ी प्रतिष्ठा का प्रतीक हैः सीएम

अंबिकापुर (दरिमा) से दिल्ली और कोलकाता के लिए सप्ताह में दो-दो दिन संचालित होंगी उड़ानें

मुख्यमंत्री साय ने अंबिकापुर-दिल्ली-कोलकाता हवाई सेवा का किया वर्चुअल शुभारंभ

टीम एक्शन इंडिया

अंबिकापुरः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के विमानन मानचित्र पर एक नया गौरवशाली अध्याय जोड़ते हुए अंबिकापुर (दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट) से दिल्ली और कोलकाता के लिए नियमित हवाई सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। वहीं अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक साक्षी बने। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में इस दिन को छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हवाई सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। दरिमा एयरपोर्ट से महानगरों के लिए विमान सेवा की लंबे समय से की जा रही मांग आज पूरी हुई है। इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेवा के प्रारंभ होने से अंबिकापुर, बिलासपुर, दिल्ली और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आवागमन सुगम बनेगा।

अंबिकापुर से दिल्ली तथा कोलकाता के लिए सप्ताह में दो-दो दिन उड़ान संचालित होगी, जिससे सरगुजा एवं बिलासपुर क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इन उड़ानों के शुरू होने से अंबिकापुर, बिलासपुर, दिल्ली और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी बेहद मजबूत होगी। सप्ताह में दो-दो दिन इन सेवाओं के संचालन से सरगुजा और बिलासपुर संभाग के नागरिकों को अब सीधे देश की राजधानी और पूर्वी भारत के प्रमुख महानगर कोलकाता तक पहुंचने में आसानी होगी।

आर्थिक और औद्योगिक विकास को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ह्विकसित छत्तीसगढ़ह्व के लक्ष्य की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, जो विकसित भारत के अनुरूप है। हवाई सेवाओं का विस्तार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत प्रदेश को लगातार लाभ मिल रहा है। हाल ही में रायपुर से रीवा के लिए भी विमान सेवा शुरू की गई है। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि पिछले बजट में रायपुर एयरपोर्ट के विस्तार हेतु 39.80 करोड़ रुपये तथा जगदलपुर एवं दरिमा एयरपोर्ट के विकास हेतु 7.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान बजट में सीजी वायु योजना के तहत 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में बिलासपुर एयरपोर्ट को ऑल वेदर ऑपरेशन की सुविधा मिली है और नाइट लैंडिंग और टेकऑफ की शुरूआत भी की गई है, जो राज्य के एविएशन सेक्टर की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एविएशन सेक्टर राज्य के आर्थिक विकास और निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

फास्टैग व्यवस्था पर उठे सवाल, एंट्री टैक्स बढ़ोतरी से सरकार का इनकार

असुविधा

» एंट्री टैक्स व्यवस्था के कारण प्रदेशवासियों को करना पड़ रहा असुविधा का सामना : जयराम

पंकज शर्मा

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के दौरान एंट्री टैक्स और फास्टैग को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि एंट्री टैक्स व्यवस्था के कारण प्रदेशवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है।

चर्चा में भाग लेते हुए विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि फास्टैग प्रणाली से जुड़ने के बाद टैक्स में कुछ वृद्धि का अनुभव हो रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि संबंधित कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तैनाती शुरू कर दी है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पंजाब के कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया है, जिससे स्थिति संवेदनशील हो सकती है।

इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि एंट्री टैक्स में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि फास्टैग से जुड़ाव के कारण लोगों को वृद्धि का आभास हो सकता है, लेकिन छोटे वाहनों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पूरे घटनाक्रम से यह संकेत मिलता है कि नई तकनीकी व्यवस्था लागू होने के साथ कुछ भ्रम और आशंकाएं उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए स्पष्ट सूचना और बेहतर प्रबंधन आवश्यक है।

घायल की मदद करने पर युवक को पुलिस ने किया सम्मानित

राजन पुरी

ऊना। मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक युवक द्वारा सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की समय रहते मदद करने पर उसे पुलिस विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है। जिला ऊना के पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ द्वारा जारी प्रशंसा पत्र के अनुसार बीती 28 फरवरी को बाल स्कूल संतोषगढ़ के पास एक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में पंजाब के रूपनगर निवासी शमशेर सिंह घायल हो गए। इस दौरान अजौली निवासी प्रदीप कुमार ने बिना समय गवाए घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संतोषगढ़ पहुंचाया, जिससे उनका समय पर इलाज संभव हो सका। ऐसी मानवता को देखते हुए पुलिस चौकी संतोषगढ़ के चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने एसपी की ओर से प्रदीप कुमार को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री नादानी से बाज आएं और बॉर्डर एरिया में हालात खराब होने से रोकें : जयराम ठाकुर

हालात

» मुख्यमंत्री के बिना विचार के फैसलों के कारण बिगड़ रहे हैं हालात

चमन शर्मा

शिमला। प्रदेश में एंट्री टैक्स को लेकर बढ़ रहे विवाद और बवाल पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बीते कल जिस प्रकार के हालात बने, वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के लोगों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। खासतौर पर बॉर्डर एरिया में हिमाचल और अन्य प्रदेशों के लोग विरोध कर रहे हैं। बीते कल ढाई घंटे से अधिक समय तक प्रदर्शन चलता रहा और करीब 4 घंटे तक पूरा हाईवे जाम रहा। प्रदर्शनकारियों ने आज से हालात और बिगड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बिना सोचे-समझे लिए गए फैसलों के कारण ही ऐसी स्थिति बनी है। इसलिए मुख्यमंत्री को पूरे मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसका सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना चाहिए।

जयराम ठाकुर ने कहा कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोग भी एंट्री टैक्स का विरोध कर रहे हैं। टैक्सी यूनियन भी इसके खिलाफ है। इसके अलावा पंजाब के लोगों ने भी विरोध जताया है और कहा है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो हिमाचल में पंजाब से लगने वाले सभी एंट्री प्वाइंट्स पर हिमाचल के वाहनों को रोका जाएगा।

इससे एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है और आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह कानून-व्यवस्था के लिए भी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि छोटी गाड़ियों के शुल्क में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। छोटे वाहनों की एंट्री फीस में लगभग 234 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पहले हिमाचल प्रदेश के यूटिलिटी वाहनों को छूट थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।

संपत्ति कर जमा करवाने का आज अंतिम दिन : मनोज कुमार

राजन पुरी

ऊना। नगर निगम ऊना के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने संपत्ति कर को 31 मार्च तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। इसके उपरांत संपत्ति कर जमा करवाने पर नियमों के अनुसार लेट फीस अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि समय से कर जमा कराने पर न केवल अतिरिक्त लेट फीस से बचा जा सकेगा, बल्कि नगर निगम की सुचारू कर प्रणाली को भी सहयोग मिलेगा। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा 5 मार्च को सभी पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर ऑनलाइन माध्यम से संपत्ति कर से संबंधित बिल भेजे दिए गए हैं।

भाजपा स्थापना दिवस को लेकर जिला स्तर पर रणनीति तय, 5 से 12 अप्रैल तक विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे

टीम एक्शन इंडिया

हमीरपुर। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने आज पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रो. प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर स्थित उनके निवास पर मुलाकात कर आगामी पार्टी कार्यक्रमों, विशेषकर 6 अप्रैल 2026 को होने वाले स्थापना दिवस के आयोजन को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा की।

इस अवसर पर जिला महामंत्री अजय रिंटू, जिला मीडिया प्रभारी विक्रमजीत सिंह बन्याल, जिला प्रवक्ता विनोद ठाकुर तथा जिला सहकारिता प्रकोष्ठ के सह-संयोजक कपिल मोहन शर्मा भी उपस्थित रहे।

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस को पूरे देश में राज्य, जिला और मंडल स्तर पर व्यापक रूप से मनाने जा रही है।

इस संदर्भ में प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने पार्टी के गौरवशाली इतिहास और विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, जिसने राष्ट्रवाद, सुशासन और अंत्योदय के मूल सिद्धांतों को अपनाते हुए देश की राजनीति में एक नई दिशा दी।

उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों से प्रारंभ हुई यह यात्रा आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हो चुकी है। पार्टी ने जनसंघ से लेकर आज तक संघर्ष, समर्पण और संगठन के बल पर देश के हर वर्ग का विश्वास जीता है।

मॉल रोड के आसपास बिखेरे गए प्रोजेक्ट लगभग 2 वर्ष से मात्र कार्य दिखाने का बहाना

चमन शर्मा

शिमला। भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला के अध्यक्ष ने नगर निगम शिमला की परिधि अर्थात शिमला मॉल रोड पर चल रहे निर्माण कार्य पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए पैसों को बेवजह बिन जरूरत वाले स्थानों पर उपयोग किया जा रहा है जो जबरदस्ती जनता पर थोपा गया कार्य है। केशव चौहान ने कहा कि मॉल रोड पर बन रहे डक्ट प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस सरकार पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा कि यह परियोजना जनता के पैसे की खुली बर्बादी का उदाहरण बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस डक्ट की अनुमानित लागत 260 करोड़ रुपये से अधिक है, जो आने वाले समय में और बढ़ने की पूरी संभावना है। केशव चौहान ने कहा कि छोटा शिमला से मॉल रोड के रास्ते में करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहे है जो पहले से ही सुचारू रूप से ठीक थे। स्मार्ट सिटी के पैसों की बर्बादी इस कदर बढ़ चुकी है कि केंद्र द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए पैसा मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों और बड़े लोगों की सहूलियत के लिए अमल में लाया जा रहा है, जो जनता के लिए होना चाहिए था वो पैसा इतनी मात्रा में इधर उधर उपयोग में लाया जा रहा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले न तो इसकी वास्तविक आवश्यकता का सही आकलन किया गया और न ही जनता को होने वाले लाभ का कोई स्पष्ट खाका प्रस्तुत किया गया।

संक्षिप्त खबरें

राज्य स्तरीय यूथ बॉक्सिंग प्रतियोगिता की हुई शुरुआत

टीम एक्शन इंडिया

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय यूथ बॉक्सिंग प्रतियोगिता का हमीरपुर के ऐतिहासिक गांधी चौक पर शुरुआत हुई जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि हमीरपुर पुलिस अधीक्षक ने किया।

मुख्य अतिथि हमीरपुर पुलिस अधीक्षक को प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव सुरेंद्र शांडिल ने हिमाचली टोपी व शाल देकर कर सम्मानित करा! जिला हमीरपुर बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण ठाकुर ने प्रदेश के अध्यक्ष राजेश भंडारी प्रदेश के महासचिव सुरेंद्र शांडिल व बॉक्सिंग के कोच नरेश कुमार को हिमाचली टोपी पहनाकर सम्मानित करा। मुख्य अतिथिअधीक्षक महोदय ने प्रतियोगिता का उद्घाटन करते वक्त अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से खिलाड़ियों व आजकल के नौजवानो मे खेल भावना पैदा होती हैं व साथ में नशे से दूर रहने की सीख भी मिलती हैं उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और इस शानदार बॉक्सिंग प्रतियोगिता के आयोजन के लिए लिये जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन को बधाई दी।

जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन हमीरपुर के महासचिव अनिल मनकोटिया ने बताया की यह बॉक्सिंग प्रतियोगिता आगामी तीन दिनों के लिये इस गांधी चौक पर आयोजित की जायेगी जिसमे हिमाचल प्रदेश से 130 के लगभग बॉक्सर भाग लेंगे।

इस प्रतियोगिता में 16 से लेकर 18 साल के लड़के व लड़कियां भाग लेंगे उन्होंने बताया कि और इस राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले बॉक्सर आगामी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो असम के गुवाहाटी में 12 अप्रैल से शुरू होंगी उसमे भाग लेंगे।

चंबा जिला में एचपी वी वैक्सीन कार्यक्रम का आगाज

हामिद खान

चंबा। जिला चंबा मे मानव पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा, डॉ. जालम भारद्वाज द्वारा किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एचपीवी एक सामान्य वायरस है, जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर) का प्रमुख कारण बन सकता है। इस वैक्सीन के माध्यम से किशोरियों को इस गंभीर बीमारी से बचाव प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अगले 5 अप्रैल तथा 12 अप्रैल को भी इस तरह के वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा. जिले के 28 स्वास्थ्य संस्थानों में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है।

कर्नल जोगिंदर पाल शर्मा बने एक्स सर्विसमैन के चेयरमैन

राजन पुरी

ऊना। ब्रह्मपुर स्थित ईसीएचएस परिसर में एक्स सर्विसमैन लीग (गगरेट-अंब) का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैप्टन बलजीत डढ़वाल की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाई गई, जबकि उनके साथ दो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहे। चुनाव में करीब 250 पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया, हालांकि मतदान प्रक्रिया के दौरान कुछ पूर्व सैनिकों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि केवल लीग के कार्ड होल्डर सदस्यों को ही चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई। इसके बावजूद करीब 150 पूर्व सैनिकों ने सक्रिय रूप से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया।

शिक्षा मंत्री ने 5.36 करोड़ से निर्माणाधीन बीडीओ कार्यालय भवन का किया निरीक्षण

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोटखाई में 5 करोड़ 36 लाख की राशि से बनने वाले विकास खंड अधिकारी कार्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरिक्षण किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह भवन कोटखाई की जनता के लिए एक बड़ी सौगात होगा। इसके बनने से विकास खंड कोटखाई में कार्यरत कर्मचारियों को सुविधा होगी और विकास कार्यों को अधिक गति मिलेगी। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में यह कार्य एक मील का पत्थर साबित होगा। गौरतलब है कि यह एक पांच मंज़िला भवन होगा जिसमें खंड विकास अधिकारी के कार्यालय एवं आवास के अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए नई तकनीक से युक्त कमरों का

निर्माण किया जा रहा है। इस भवन के प्रथम तल पर एक पुस्तकालय का निर्माण भी किया जा रहा है जिससे पंचायती राज से जुड़े प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों सहित जनसामान्य को भी लाभ होगा। इस भवन में लिफ्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही कैंटीन का भी प्रावधान इस भवन में रखा गया है। इस भवन की सबसे ऊपरी

मंज़िल में पंचायत समिति हॉल का निर्माण भी किया जाना है, जिसमें समय-समय पर महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन हो सकेगा। रोहित ठाकुर ने इस भवन के निर्माण से जुड़े सभी अधिकारियों एवं निर्माणकर्ताओं को निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। साथ ही यह भी बताया कि जुब्बल नावर कोटखाई में चल रहे विकास कार्यों की श्रृंखला में खंड विकास अधिकारी कोटखाई का कार्यालय एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

नशा निवारण केंद्र पर मरीज का कीमती सामान हड़पने का आरोप

राजन पुरी

ऊना। पुलिस थाना टाहलीवाल के तहत बाथड़ी स्थित एक नशा निवारण केंद्र के संचालक पर मरीज का कीमती सामान वापस न करने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में नशा निवारण केंद्रों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

पुलिस को दी शिकायत में पंजाब के बलाचौर निवासी राकेश लाल ने बताया कि वह नशे का आदी था और इलाज के लिए सात माह तक बाथड़ी स्थित न्यू विजन नशा निवारण केंद्र में भर्ती रहा। भर्ती के दौरान केंद्र प्रबंधन ने उसका कीमती सामान अपने पास सुरक्षित रखने के नाम पर जमा करवा लिया था और आश्वासन दिया था कि डिस्चार्ज के समय उसे वापस कर दिया जाएगा।

शिकायतकर्ता के अनुसार जब वह इलाज पूरा कर घर लौटने लगा, तो केंद्र प्रबंधन ने उसका सामान लौटाने से इनकार कर दिया। इस सामान में करीब 8.77 ग्राम वजन की सोने की अंगूठी शामिल है। इसके अलावा उसका आधार कार्ड भी केंद्र के पास ही रह गया।

अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में भारत-यूरोपीय संघ संसदीय मैत्री समूह की पहली बैठक सम्पन्न

टीम एक्शन इंडिया

हमीरपुर। भारत-यूरोपीय संघ संबंधों पर हाल ही में गठित संसदीय मैत्री समूह की पहली ऐतिहासिक बैठक आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में आयोजित हुई।

इस बैठक में यूरोपीय संसद के भारत संबंधी प्रतिनिधिमंडल (ष्ठ-ढ्ढह) ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व चेयरपर्सन एंजेलिका नीब्लर (जर्मनी, ईपीपी समूह) तथा उपाध्यक्ष नील्स फ्लेमिंग ने किया।

भारतीय पक्ष से सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में गठित संसदीय मैत्री समूह के 11 सदस्यों ने सहभागिता की। यह बैठक नवगठित मैत्री समूह के अंतर्गत पहली औपचारिक संसदीय सहभागिता रही, जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच

संस्थागत संबंधों की गहराई को दर्शाती है। बैठक जनवरी 2026 में आयोजित भारत-ईयू शिखर सम्मेलन की भावना तथा उसके बाद द्विपक्षीय संबंधों में हुए व्यापक उन्नयन के संदर्भ में आयोजित की गई।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह भारत की संसदीय कूटनीति के लिए गर्व का क्षण है। इस मैत्री समूह का गठन और यूरोपीय साझेदारों के साथ यह पहली बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सतत मार्गदर्शन का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने तथा दोनों पक्षों की संसदों और जनता के बीच सेतु बनाने के लिए ऐसे संवाद आगे भी जारी रहेंगे।

भारत-ईयू अंतर-संसदीय बैठक के 16वें संस्करण के दौरान आयोजित इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई।

व्यापार एवं आर्थिक संबंधों के तहत भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते पर हुई ऐतिहासिक प्रगति का स्वागत किया गया, जिसे लगभग 25 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त बाजार और करीब दो अरब लोगों को कवर करने वाली विश्व की प्रमुख आर्थिक साझेदारियों में से एक बताया गया।

घर में घुसकर मारपीट व धमकी देने का मामला दर्ज, पांच के खिलाफ केस

राजन पुरी

ऊना। पुलिस थाना हरोली के तहत बढेड़ा में घर एक मारपीट व धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में विकास राणा निवासी बढेडा ने बताया कि बीते सोमवार को उनकी पत्नी अंकिता राणा, शिव कुमार, जितेंद्र राणा, करनैल और एक वकील नीरज कुमार जबरन उनके घर में घुस आए। उस समय घर पर उनके बुजुर्ग माता-पिता मौजूद थे। आरोप है कि सभी ने मिलकर उनके माता-पिता के साथ गाली-गलौच, धक्का-मुक्की और मारपीट की तथा जान से मारने की धमकियां दीं। साथ ही आरोपियों ने कथित तौर

पर दहेज का सामान और कार वापस न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनका और उनकी पत्नी के बीच मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसके बावजूद आरोपियों ने जबरदस्ती घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। घटना के समय शिकायतकर्ता घर पर मौजूद नहीं था। डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर पांच के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फोरलेन पर लगते जाम की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की : सांख्यान

टीम एक्शन इंडिया

हमीरपुर। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया कॉर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) पर निशाना साधते हुए कहा है कि अरबों की लागत से बने कीरतपुर साहिब से नेरचौक फोरलेन पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बेसुध पड़ा है।

संदीप सांख्यान ने कहा इस फोरलेन पर बिलासपुर के ग्राम पंचायत टाली से लेकर गांव मेहला तक लंबा जाम लगना और इस फोरलेन पैच में पहाड़ी की तरफ से लगातार पत्थरों और मिट्टी का गिरना बड़े हादसे को न्योता दे रहा है।

संदीप सांख्यान ने कहा कि बीती तीन बरसातों में भी यहां पर कई हादसे हो चुके हैं लेकिन एन एच ए आई बिल्कुल बेसुध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है और बरसात में तो यहाँ की स्थिति और भी भयानक हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस फोरलेन पर जो स्थिति बनी है उससे केंद्र सरकार का परिवहन मंत्रालय भी बेसुध पड़ा है। संदीप सांख्यान ने कहा कि ऊपर से यहां से आने-जाने वाले यात्रियों को लंबे जाम के बावजूद फोरलेन की जगह टू लेन से काम चलाना पड़ता है। जबकि टोल फोरलेन की सुविधा का वसूला जाता है और इसमें कोई रियासत यहां पर नहीं दी जाती है, जोकि फोरलेन पर गाड़ी चलाने

की एवज में यात्रियों को मिलनी चाहिए। संदीप सांख्यान ने कहा कि केंद्र सरकार का सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इस फोरलेन बनाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ताकि उनकी गलतियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और उसको बनाने वाली कम्पनी को पैनेलाइज किया जा सके।

हिमाचल की जनता की छोड़ पंजाब का समर्थन कर रहे विधायक सत्ती

राजन पुरी

ऊना। प्रदेश कांग्रेस में दूसरी बार उपाध्यक्ष बनने के बाद पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने ऊना में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा और स्थानीय विधायक सतपाल सत्ती पर जमकर निशाना साधा। रायजादा ने भाजपा की नीतियों और कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पार्टी के नेता प्रदेश के असल जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाकर अनावश्यक और भ्रामक विषयों को तूल दे रहे हैं।

टोल टैक्स के मुद्दे पर रायजादा ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा बाहरी राज्यों के वाहनों पर जो टैक्स बढ़ाया गया है, उससे प्रदेशवासियों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है। फिर भी भाजपा नेता इस मुद्दे को गलत तरीके से पेश कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता सत्ती पंजाब के हितों की वकालत करते नजर आ रहे हैं, जबकि उन्हें हिमाचल के हितों की रक्षा करनी चाहिए। रायजादा ने कहा कि पंजाब में हिमाचल की निजी बसों से तीन गुना अधिक टैक्स वसूला जाता है, लेकिन इस विषय पर भाजपा कभी आवाज नहीं उठाती। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा की प्राथमिकताएं प्रदेश के हितों से मेल नहीं खातीं।

चंबा वन विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत, कार्रवाई की मांग

हामिद खान

चंबा। वन विभाग चंबा के खिलाफ एक लिखित शिकायत सामने आई है, जिसमें विभाग के एक कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह शिकायत वन मंडलाधिकारी चंबा को संबोधित करते हुए भाजपा मंडल करीयां की ओर से दी गई है।

इस संदर्भ में सोमवार को भाजपा मंडल करीयां का एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा मंडल अध्यक्ष विनायक रैणा की अगुवाई में वन मंडल अधिकारी चंबा से मिला तथा उन्हें इस बारे ज्ञापन सौंपा।

शिकायत में बताया गया है कि वन विभाग के एक कर्मचारी द्वारा भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य तथा पूर्व में अनुसूचित जाति एवं

जनजाति विकास निगम के उपाध्यक्ष रहे जय सिंह के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया। इस घटना को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं और लोगों में रोष व्याप्त है।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त कर्मचारी के खिलाफ पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया।

एनटीपीसी कोलडैम द्वारा आयोजित मशीन निटिंग एवं ब्यूटी पार्लर, प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन

टीम एक्शन इंडिया

बिलासपुर। महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य एनटीपीसी कोलडैम द्वारा अपने नैगम सामाजिक दायित्वके अंतर्गतग्राम पंचायत सोझा (मंडी) एवं जूणी (शिमला) में संचालित चार.चार माह के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यकर्मों का समापन सोमवार को किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एनटीपीसी कोलडैम के सौजन्य से हिमकॉन शिमला द्वारा सम्पन्न किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मानव संसाधन प्रमुख, एनटीपीसी कोलडैम, मंगला हरीन्द्रन ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण.पत्र प्रदान किए। साथ ही, प्रतिभागियों को निटिंग मशीन एवं ब्यूटी पार्लर किट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर एनटीपीसी कोलडैम के सीएसआर विभाग से वरिष्ठ प्रबंधक डॉ. अंजुला अग्रवाल, सहायक प्रबंधक पूरन सिंह, हिमकॉन से डिप्टी मैनेजर

अमर वर्मा, समन्वयक मनोज एवं अमित शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत घरयाना संजय श्रीवास्तव तथा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली प्रशिक्षिकाएं मुस्कान एवं सुनीता भी उपस्थित रहीं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम नें ग्राम पंचायत सोझा एवं जुणी की 50 महिलाओं को लाभान्वित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को नवीन कौशल सिखाकर उन्हें स्वावलंबी बनाना तथा रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सभी महिलाओं ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं इसकी खूब सराहना की। प्रतिभागियों ने कहा कि इस कार्यक्रम से उनकी सोच को एक नई दिशा मिली है तथा भविष्य में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। एनटीपीसी कोलडैम स्थानीय समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। सीएसआर के अंतर्गत संचालित ऐसे कौशल विकास कार्यक्रम न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैंए बल्कि समाज के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

बिलासपुर शहर में इस बार वार्ड नंबर आठ, नौ और दस ओपन

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने जिला बिलासपुर में आगामी नगर निकाय चुनाव 2026 के दृष्टिगत नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के लिए वार्डवार आरक्षण सूची जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार नगर परिषद श्री नयना देवी जी क्षेत्र में कुल 7 वार्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें एक वार्ड अनुसूचित जाति महिलाएं तीन वार्ड महिलाओं तथा तीन वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस परिषद के अंतर्गत देवी, तारा तथा कालिका वार्ड सामान्य वर्ग में, दुर्गा वार्ड अनुसूचित जाति महिलाए जबकि शीतला, शक्ति तथा अंबिका वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नगर परिषद घुमारवीं क्षेत्र में कुल 9 वार्डों में एक वार्ड अनुसूचित जाति, एक वार्ड अनुसूचित जाति महिला, चार वार्ड महिलाओं तथा तीन वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अंतर्गत बड्डू, टिक्करी, इंदिरा और दकड़ी वार्ड महिलाओं के लिए, अंबेडकर, हारकुकार और कल्याणा वार्ड सामान्य वर्ग के लिए, जगदंबा वार्ड अनुसूचित जाति महिला तथा बजोहा वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद बिलासपुर में कुल 11 वार्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें एक वार्ड अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जाति महिला, पांच वार्ड महिलाओं तथा चार वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस परिषद के अंतर्गत निहाल, रौड़ा, कोसरियां, चंगर तथा गुरूद्वारा वार्ड महिलाओं के लिए, स्टेडियम वार्ड अनुसूचित जाति महिला, लखनपुर वार्ड अनुसूचित जाति तथा मेन मार्केट, लक्ष्मी नारायण, टाउन हॉल और धौलरा वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह नगर पंचायत तलाई में कुल 7 वार्डों में एक वार्ड अनुसूचित जाति, एक वार्ड अनुसूचित जाति महिला, तीन वार्ड महिलाओं तथा दो वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं।

एससीएसटी विकास निधि विशेष कानून, बनाने की मांग को लेकर 1 अप्रैल से सामाजिक न्याय यात्रा

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निधि विशेष कानून बनाने की मांग को लेकर 1 अप्रैल 2026 से विधानसभा स्तर पर सामाजिक न्याय यात्रा की शुरु की जा रही है। सामाजिक न्याय यात्रा के दौरान हर घर दस्तक दी जाएगी और 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर संबंधित विधायक के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश में एससीएसटी विकास निधि कानून के लिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की जाएगी कि वह पार्टी चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदे अनुसार हिमाचल प्रदेश में एससीएसटी विकास निधि कानून की प्रक्रिया शुरू करे। प्रैस को जारी बयान में सुखदेव विश्वप्रेमी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में एससीएसटी विकास निधि विशेष कानून्

बनाने की मांग को लेकर सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत जिला चंबा से 1 अप्रैल को की जाएगी। उन्होंनें कहा कि हिमाचल प्रदेश में एससीएसटी विकास निधि कानून बनाने की मांग को लेकर मार्च 2023 में एक राज्य गठबंधन का गठन किया गया। जिसके उपरांत प्रदेश में अनुसूचित जाति उप योजना विकास कार्यक्रम की स्थिति पर पिछले 5 वर्षों का अध्ययन किया गया और इस पर एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके आधार पर 2023 में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और जनजातीय विकास मंत्री के साथ चर्चा की गई और इनके माध्यम से पैरवी की शुरुआत की गई। इसी क्रम में राज्य गठबंधन के प्रतिनिधि एससीएसटी के दोनों पार्टियों के विधायकों के साथ हिमाचल प्रदेश में एससीएसटी विकास निधि कानून बनाने के लिए विचार विमर्श किया और 15,17 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ 1 फरवरी 2024 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एससीएसटी, पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रभारी डॉ. के राजू और अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री से मिल और मुख्यमंत्री प्रदेश में एससीएसटी विकास निधि कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करने गुजारिश की। राज्य गठबंधन द्वारा 14 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के सुझाव पर हिमाचल प्रदेश में एससीएसटी विकास निधि कानून का ड्राफ्ट बिल तैयार करके भोरंज विधानसभा के विधायक डॉ.

राहत योजना: दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस इलाज': डीसी

धर्मशाला। पीएम राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनजागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कांगड़ा द्वारा आज सोमवार को धर्मशाला स्थित उपायुक्त सभागार में एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त कांगड़ा, हेमराज बैरवा ने की।उपायुक्त ने कहा कि यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक के इलाज का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर पीड़ित को सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती करवाना आवश्यक है,

फोरलेन पर लगते जाम की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की: संदीप सांख्यान

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया कॉर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) पर निशाना साधते हुए कहा है कि अरबों की लागत से बने कीरतपुर साहिब से नेरचैक फोरलेन पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बेसुध पड़ा है। संदीप सांख्यान ने कहा इस फोरलेन पर बिलासपुर के ग्राम पंचायत टाली से लेकर गांव मेहला तक लंबा जाम लगना और इस फोरलेन पैच में पहाड़ी की तरफ से लगातार पत्थरों और मिट्टी का गिरना बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। संदीप सांख्यान ने कहा कि बीती तीन

बरसातों में भी यहां पर कई हादसे हो चुके हैं लेकिन एनएचएआई बिल्कुल बेसुध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है और बरसात में तो यहाँ की स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फोरलेन पर जो स्थिति बनी है उससे केंद्र सरकार का परिवहन मंत्रालय भी बेसुध पड़ा है। संदीप सांख्यान ने कहा कि ऊपर से यहां से आने.जाने वाले यात्रियों को लंबे जाम के बावजूद फोरलेन की जगह टू लेन से काम चलाना पड़ता है जबकि टोल फोरलेन की सुविधा का वसूला जाता है और इसमें कोई रियासत यहां पर नहीं दी जाती है, जोकि फोरलेन पर गाड़ी चलाने की एवज में यात्रियों को मिलनी चाहिए। संदीप सांख्यान ने कहा कि केंद्र सरकार का सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इस फोरलेन बनाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ताकि उनकी गलतियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और उसको बनाने वाली कम्पनी को पैनेलाइज किया जा सके।

पेट्रोल, डीज़ल एवं घरेलू गैस की कोई कमी नहीं : अनुराग चन्द्र शर्मा

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू। उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में पेट्रोल, डीज़ल एवं घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर लगभग 3,04,251 लीटर पेट्रोल तथा 3,72,417 लीटर डीज़ल उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिले की 16 गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति भी नियमित रूप से हो रही है। उन्होंने बताया कि 30 मार्च 2026 को 1764 घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त हुए हैं, जबकि एजेंसियों के पास 2763 घरेलू गैस सिलेंडर एवं 191 वाणिज्यिक गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं।

उपायुक्त ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीति के अनुसार वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने ढाबा एवं होटल संचालकों से अपील की कि वे ईंधन के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें, ताकि वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों पर निर्भरता कम हो सके।

उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद करें। साथ ही गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए टोल-फ्री नंबर पर एक बार ही मिस कॉल करने की सलाह दी, ताकि अनावश्यक दबाव से बचा जा सके।

पांगी के 24 वर्ष के बेटे ने पास की टीजीटी मेडिकल परीक्षा

टीम एक्शन इंडिया
खेमचंद शास्त्री

मंडी। कहते हैं कि यदि दिल में कुछ करने की तमन्ना हो तो मंजिल मिल ही जाती है। ऐसा ही कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र पांगी के रेई गांव के 24 वर्षीय देवी सिंह ने। पांगी के साधारण परिवार से संबंध रखने वाले इस बेटे ने टीजीटी मेडिकल परीक्षा पास कर युवा पीढ़ी के लिए मिसाल पेश की है। देवी सिंह वर्तमान समय सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में एमएससी अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं। इनके पिता मेहनत मजदूरी करते हैं जबकि माता ग्रहणी है। इनके दो भाई है। एक बड़ा व दूसरा इनसे छोटा है। स्कूली शिक्षा गांव में हासिल करने के उपरांत इन्होंने बल्लभ महाविद्यालय मंडी से बीएससी तथा विजय मेमोरियल कॉलेज नेर चौक से(ह्व.श्वस्र) बीएड की पढ़ाई पूरी की। इनकी पढ़ाई इनके ननिहाल के सानिध्य में हुई।

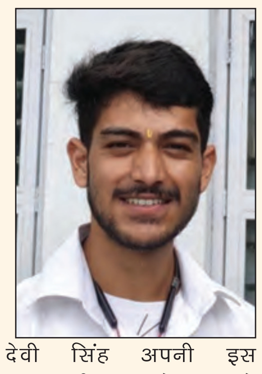

देवी सिंह अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने नाना, नानी मामा और ननिहाल के सदस्यों व अपने शिक्षको को देते हैं। इनका कहना है कि एमएससी के साथ इन्होंने मेडिकल परीक्षा की तैयारी दिन-रात कड़ी मेहनत करके की तब जाकर इन्हें यह कामयाबी हासिल हुई है। युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए देवी सिंह का कहना है कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर यदि हम पूरी तरह से उस पर फोकस करके लगन व ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो कामयाबी अवश्य हासिल होती है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जीवन ठाकुर का जोगिंद्रनगर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

टीम एक्शन इंडिया
संगराय

जोगिंद्रनगर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष जीवन ठाकुर का सोमवार को अपने गृह क्षेत्र जोगिंद्रनगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने घटासनी से जोगिंद्रनगर तक जगह जगह फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया।इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जीवन ठाकुर ने कहा कि जो पद मुझे आज मिला है वो आपसब की मेहनत का नतीजा है। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज मुझे जो मान सम्मान दिया है उसका में दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं।ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाने पर शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमति सोनिया गांधी, लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष विनय कुमार का आभार व्यक्त किया है।उन्होंने कहा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ काम कर रही है और आगामी चुनावों में मिशन दोहराने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे।ठाकुर ने कहा कि जो व्यक्ति पूरी मेहनत और लग्न से जनता के कार्य करते है उनपर आरोप प्रत्यरोप लगना आम बात है।इस से डरने की जरूरत नहीं है।उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है आशा करता हूं कि आगे भी इस प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा।ठाकुर ने कहा कि स्थानीय विधायक ने 2017 के चुनावों से पहले क्षेत्र की जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे लेकिन जितने के बाद सब भूल गए।उन्होंने कहा कि विधायक क्षेत्र की जनता को आजतक गुमराह करते आ रहें है।उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पिछले तीन सालों में जोगिंद्रनगर में जो भी विकास के कार्य हुए है उन्हें जनता तक पहुंचाये तथा पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ता एक जुट होकर कार्य करें।इस अवसर पर मनरेगा बचाओ अभियान संघर्ष समिति जोगिंद्रनगर के प्रभारी ठाकुर हीरा पाल सिंह,वरिष्ठ कांग्रेस नेता रंजन शर्मा, प्यार चंद,स्वर्ण कुमार,बीरबल ठाकुर ने भी उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

एचपीबीओएसई ने 10वीं-12वीं की अस्थायी उत्तर कुंजियां जारी

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के सभी विषयों की अस्थायी उत्तर कुंजियां जारी कर दी हैं। इससे विद्यार्थियों को परिणाम घोषित होने से पहले ही बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करने का अवसर मिलेगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक परीक्षा के 24 से 48 घंटे के भीतर संबंधित विषय की उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने प्रदर्शन का समय रहते आकलन करने में मदद देना है।

मंडी के पंचवक्त्र मंदिर से जूते चोरी: चौहटा बाजार में चोर पकड़ा गया, हाईवोल्टेज ड्रामा

टीम एक्शन इंडिया
खेमचंद शास्त्री

मंडी। मंडी के प्रसिद्ध पंचवक्त्र महादेव मंदिर में जूते चोरी का एक मामला सामने आया है। चोरी के बाद चौहटा बाजार में चोर को पकड़ने के दौरान हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार कोटली निवासी विजय कुमार अपने दोस्त के साथ सुबह मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन के बाद जब वे वापस लौटे, तो विजय कुमार के लगभग 7 हजार रुपये कीमत के जूते गायब थे। उनके दोस्त के जूते वहीं मौजूद थे। विजय कुमार ने तुरंत मंदिर परिसर में मौजूद गार्ड को

सूचना दी और पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति जूते लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। इसी बीच विजय कुमार चौहटा बाजार गए और वहां से उसी कीमत के नए जूते खरीदे। वापस लौटते समय उनकी नजर अचानक उसी संदिग्ध युवक पर पड़ी जिसका हुलिया सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। विजय कुमार ने तुरंत उस युवक को पकड़ लिया जिसके बाद मौके पर हंगामा शुरू हो गया। गुस्से में उन्होंने चोर की धुनाई भी कर दी।

पर्यावरण मानकों से समझौता नहीं होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती के निर्देश : अपूर्व देवगन

टीम एक्शन इंडिया
खेमचंद शास्त्री

मंडी। उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय के वीसी कक्ष में एनजीटी से संबंधित विभिन्न मामलों तथा सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) पर रोक को कड़ाई से लागू किया जाए तथा नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए निरीक्षण, चालान, प्लास्टिक जब्ती तथा प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजारों, संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर नियमित निरीक्षण अभियान चलाए जाएं तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर पूर्ण रोक सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण को प्राथमिकता देते हुए इसे सड़क निर्माण, सीमेंट संयंत्रों तथा अन्य स्वीकृत माध्यमों के माध्यम से उपयोग में लाने के निर्देश दिए। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि तरल एवं ठोस कचरे का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना नगर निकायों की जिम्मेदारी है तथा इस कार्य में संलग्न सभी डिस्लजर एवं ठेकेदारों का नगर निकायों तथा खंड (ब्लॉक) कार्यालयों में पंजीकरण अनिवार्य होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सेप्टिक टैंक से निकाले गए मल को केवल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ही डंप किया जाए तथा इसे खुले में, नालों अथवा खड्डों में बहाने की किसी भी घटना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपमंडल अधिकारियों (एसडीएम) एवं खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि सेप्टिक टैंक से निकाले गए मल का निस्तारण केवल अधिकृत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अथवा यांत्रिक डिस्लजर के माध्यम से ही किया जाए। उन्होंने कहा कि गोहर जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए

हरिचंद शर्मा बने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, क्षेत्र में खुशी की लहर

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू। लंबे समय से कांग्रेस संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे वरिष्ठ नेता हरिचंद शर्मा को हाल ही में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति से उनके गृह क्षेत्र सहित समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कार्यकर्ताओं ने इसे उनकी वर्षों की मेहनत, निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण का परिणाम बताया है हरिचंद शर्मा पिछले लगभग 37 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर

अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में वे मनाली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वर्ष 2009 से जिला कांग्रेस कमेटी के निर्वाचित सदस्य के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत युवा कांग्रेस से की और वर्ष 1999 से 2008 तक जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वे ग्राम पंचायत जगतसुख के प्रधान, जिला परिषद सदस्य तथा जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान जिला परिषद कुल्लू को कई बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी प्राप्त हुआ। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और कड़े मुकाबले में बहुत कम अंतर से पराजित हुए। इसके बावजूद उन्होंने संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी और निरंतर पार्टी गतिविधियों में सक्रिय रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हरिचंद शर्मा जमीनी स्तर के नेता हैं और संगठन को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी नियुक्ति से कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में नई ऊर्जा मिलेगी। उनकी नियुक्ति पर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और समर्थकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है तथा आशा जताई है कि वे अपने नए दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे।

26 मई से होगी सामान्य प्रवेश परीक्षा शुरू

टीम एक्शन इंडिया
खेमचंद शास्त्री

मंडी। सरदार पटेल विश्व विद्यालय ने स्नातकोतर, बीबीए तथा बीसीए के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (कामन एंट्रेस टेस्ट) का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रवेश परीक्षा की तिथी से लेकर प्रवेश परीक्षा शुल्क का विवरण भी जारी कर दिया है। छह अप्रैल से विश्व विद्यालय प्रशासन इसके लिए आनलाइन फार्म उपलब्ध करवाएगा। चार मई तक आनलाइन आवेदन जमा करने के साथ साथ शुल्क भी जमा करना होगा। 19 मई को एडमिट कार्ड जनरेट किए जाएंगे। 26 मई को एमएससी केमिस्ट्री, एमए राजनीतिक विज्ञान, एमएससी

फिजिक्स तथा एमए हिस्ट्री विषय के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। इसी तरह 27 मई को एमबीए, बीबीए बीसीए तथा एमसीए के लिए परीक्षा होगी। 28 मई को एमएससी जूलाजी, एमएससी बाटनी, 29 मई को एमएससी मैथ, एमकाम तथा तीस मई को एमए अंग्रेजी व एमए हिंदी विषय की सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा शुल्क भी विभिन्न वर्गों के आवेदकों के लिए अलग अलग निर्धारित है। एमबीए के लिए मंडी व कांगड़ा में प्रवेश परीक्षा केंद्र होंगे। इसी तरह बीबीए, बीसीए, एमसीए, एमए अंग्रेजी, हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, एमकाम, एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलाजी, मैथेमेटिक्स व बाटनी की प्रवेश परीक्षा के लिए मंडी कुल्लू, सरकाघाट व जोगिंद्रनगर में परीक्षा केंद्र होंगे। सामान्य प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 26 से 30 मई तक सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

एन एच 305 के शीघ्र उन्नयन व मरम्मत को लेकर विधायक सुरेंद्र शौरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू। बंजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र शौरी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके कार्यालय में भेंट की। इस दौरान उन्होंने ह॥-305 की दयनीय स्थिति को प्रमुखता से उठाते हुए इसके शीघ्र उन्नयन एवं मरम्मत के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करवाने की माँग की। विधायक शौरी ने विशेष रूप से बरसात के बाद सड़क की बिगड़ी हालत से अवगत करवाते हुए इस मार्ग के लिए विशेष बजट जारी करने का आग्रह किया, ताकि क्षेत्र की जनता को सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने औट से बंजार की ओर एन एच 305 के लिए तैयार की जा रही डीपीआर को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार से डीपीआर प्राप्त होते ही इसे प्राथमिकता के साथ स्वीकृति दी जाएगी।

साथ ही, औट-बंजार मार्ग पर एनएच डीपीआर के दौरान उत्पन्न हुए सिंकहोल की विवेचना रिपोर्ट को भी शीघ्र तैयार करने के निर्देश देने का भरोसा दिया। विधायक शौरी ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार के सकारात्मक रुख से एन एच 305 के कार्यों में तेजी आएगी और क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान शीघ्र होगा।

पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू। पीएम पोषण शक्ति निर्माण (मिड डे मील) योजना की जिला संचालन एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सुनील ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी कुंदन लाल, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक का संचालन उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सुनील कुमार ने किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 7 शिक्षा खंडों के अंतर्गत 1006 प्री-प्राइमरी, प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी विद्यालयों में कुल 35,118 विद्यार्थियों को मिड-डे मील प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि सभी 1006 विद्यालयों में किचन गार्डन भी स्थापित किए गए हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों को बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी विद्यालयों में निर्धारित मेनू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिला कुल्लू को इस योजना के अंतर्गत 7 करोड़ 49 लाख 64 हजार 452 रुपये का बजट आवंटित किया गया है।उन्होंने योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के साथ साथ भोजन की गुणवत्ता एवं पोषण स्तर की निगरानी, निर्धारित दिशा-निर्देशों के पालन, स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण तथा बजट उपयोग के लिये भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये।

सीबीएसई के नाम पर हिमाचल शिक्षा बोर्ड को खत्म करने की साजिश : राकेश जम्बाल

टीम एक्शन इंडिया
खेमचंद शास्त्री

मंडी। सुंदरनगर से भाजपा के विधायक व मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्बाल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार के फैसलों पर जोरदार हमला बोलते हुए इसे हिमाचल के अपने शिक्षा बोर्ड को कमजोर करने की सुनियोजित साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने का निर्णय बिना किसी ठोस अध्ययन और दूरदर्शिता के जल्दबाजी में लिया गया है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में प्रदेश के विद्यार्थियों और शिक्षा तंत्र को भुगतना पड़ेगा। सदन में सरकार द्वारा दिए गए जवाब का हवाला देते हुए जमवाल ने कहा कि प्रदेश के लगभग 151 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को सीबीएसई से जोड़ा जा रहा है और इन्हें शैक्षणिक सत्र

2026-27 से सीबीएसई के अंतर्गत संचालित किया जाएगा, जिसके लिए प्रति विद्यालय लगभग ?45,000 खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर यह निर्णय किस आधार पर लिया गया और क्या इसके लिए कोई व्यापक शैक्षणिक या प्रशासनिक अध्ययन किया गया है। जमवाल ने कहा कि करीब 151 ऐसे विद्यालय, जो पहले हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़े थे, उन्हें सीबीएसई में शामिल करना सीधे तौर पर अपने ही बोर्ड को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से पढ़ा हुआ विद्यार्थी किसी भी स्तर पर सीबीएसई के विद्यार्थियों से कम है, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश के छात्र वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्वसनीय संस्था रही है, जिसने प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की है,

त्रिलोकपुर मंदिर परिसर में श्रद्धालु की अचानक मौत

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बाला सुंदरी मंदिर के समीप स्थित ललिता माता मंदिर में यह दुखद घटना सामने आई। श्रद्धालु दर्शन के लिए लाइन में खड़ा था, तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा।

घटना के बाद वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई और तुरंत सहायता के प्रयास शुरू किए गए। मृतक की पहचान 36 वर्षीय राजेश के रूप में हुई है, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद क्षेत्र का निवासी था। बताया जा रहा है कि लाइन में खड़े रहने के दौरान उसे अचानक चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर गया। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया

। राजेश की अचानक मृत्यु से उसके परिवार पर गहरा दुख छा गया है। वह अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गया है, जिनके लिए यह घटना बेहद पीड़ादायक साबित हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। परिजनों को भी सूचना दे दी गई है और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

प्रारंभिक जांच में इसे हार्ट अटैक का मामला माना जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं भविष्य के विकास का आधार-संजय अवस्थी

टीम एक्शन इंडिया
मनीष

सोलन। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं भविष्य के विकास का आधार बनेगी। संजय अवस्थी गत दिवस अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सूरजपुर में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत 7.06 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले घनागुघाट से कुन्नी छिब्बर पिपलूघाट मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर पिपलूघाट में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आजीविका भवन की आधारशिला भी रखी। संजय अवस्थी ने कहा कि विकास की गति को आगे बढ़ाने में सड़कें अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ सड़क नेटवर्क लोगों की सुगम

आवाजाही व व्यापार बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि प्रदेश के प्रत्येक गांव तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचाई जाए। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, बागवानों व पशुपालकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती से उगाए जाने वाली गेहूं, मक्की, अदरक व हल्दी की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में आशातीत बढ़ौतरी की गई है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि पशुपालकों की आर्थिकी को और सुदृढ़ बनाने के लिए गाय व भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया गया है। संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश के कमज़ोर वर्गों तक विकास को पहुंचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कमज़ोर वर्ग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

जीसीटीई धर्मशाला के छात्र-शिक्षकों का 'नवरंग 2026' में शानदार प्रदर्शन

टीम एक्शन इंडिया

धर्मशाला। जी.सी.टी.ई. धर्मशाला के छात्र-शिक्षकों ने रैत स्थित द्रोणाचार्य पी.जी. कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजित 'नवरंग 2026' कार्यक्रम में उत्साह और जोश के साथ भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. युवराज सिंह पठानिया के नेतृत्व तथा डॉ. प्रियंका के मार्गदर्शन में टीम ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रभावी प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक और प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों में हिस्सा लिया, जहां प्रतिभागियों ने रचनात्मकता, ज्ञान और खेल भावना का परिचय दिया। जीसीटीई की टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किए। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हीना और तरुण ने उत्कृष्ट समन्वय और ज्ञान का परिचय देते हुए द्वितीय स्थान हासिल किया। वहीं शतरंज प्रतियोगिता में गरिमा कंवर ने अपनी रणनीतिक सोच के बल पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। कबड्डी में राहुल ठाकुर के नेतृत्व वाली टीम, जिसमें ललित नेगी, शौर्यवीर, प्रवीण ठाकुर, मुकेश ठाकुर, अमन, संगम, उमित शर्मा, गगनीश ठाकुर, रविंदर राणा, रितिक चाढ़क और राजू शामिल थे, ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता का खिताब जीता। इसके अलावा समूह नृत्य प्रतियोगिता में साहिल शर्मा, अजय, निशांत शर्मा, हैरी रांटा, निकेश, मीनाक्षी ठाकुर, सुदिक्षा, साधना ठाकुर, राजेश्वरी और मोनिका देवी की टीम ने ऊर्जावान प्रस्तुति देकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को ट्रॉफी, पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

आईआईटी मंडी ने मनाया 17वां स्थापना दिवस, नवाचार एवं शोध के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता दोहराई

टीम एक्शन इंडिया
खेमचंद शास्त्री

मंडी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, देश के अग्रणी आईआईटी संस्थानों में से एक, ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उद्योग, शिक्षाविद् और वैश्विक शोध जगत के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने भाग लिया और भारत के भविष्य के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं उभरती प्रौद्योगिकियों की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। आईआईटी मंडी विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार का अग्रणी केंद्र बन चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मटेरियल्स तथा इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग में अत्याधुनिक शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है। यह संस्थान 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य कर रहा है। वर्षों में संस्थान एक शोध-केंद्रित विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ है, जो अनुभवात्मक शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है तथा अपने आदर्श वाक्य 'स्केलिंग द हाइट्स' को निरंतर

साकार कर रहा है। इस कार्यक्रम में पद्म भूषण से सम्मानित इंफोसिस लिमिटेड के सह-संस्थापक श्री क्रिस गोपालकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि स्टैनफोर्ड रोबोटिक्स लैब, अमेरिका के निदेशक प्रो. उस्सामा खातिब विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में आईआईटी मंडी के संस्थापक निदेशक प्रो. टिमोथी गोंसाल्वेस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी तथा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक शामिल थे आईआईटी मंडी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा, 'आईआईटी मंडी का 17वां स्थापना दिवस न केवल संस्थान की प्रगति पर चिंतन का अवसर है, बल्कि 'षोडश' के सार को भी दर्शाता है, जो युवा ऊर्जा, सृजनशीलता और निरंतर विकास का प्रतीक है। वर्षों में आईआईटी मंडी क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर सिस्टम्स और इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग में अग्रणी शोध केंद्र के रूप में उभरा है, जिसे ?120 करोड़ से अधिक के शोध अनुदानों का समर्थन प्राप्त है। नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता पर हमारा निरंतर फोकस 'फ्यूचर-रेडी लीडर्स' तैयार कर रहा है, जो तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ' मुख्य अतिथि श्री क्रिस गोपालकृष्णन ने अपने मुख्य संबोधन में कहा, 'हम एक 'इंटेलिजेंस रिवोल्यूशन' के दौर में हैं

संक्षिप्त खबरें

बास्केटबॉल अंडर-19 बॉयज एवं गर्ल्स के ट्रायल में पहुंचे 40 खिलाड़ी

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन। जिला मुख्यालय नाहन में बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा अंडर-19 बॉयज और गर्ल्स के लिए बास्केटबॉल के ट्रायल आयोजित किए गए , जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चयनित खिलाड़ी हमीरपुर में होने जा रही राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगें। मीडिया से बात करते हुए जिला सिरमौर बास्केटबॉल संघ की चयन समिति सदस्य इकबाल कौर ने बताया कि संघ की ओर से अंडर-19 बॉयज और गर्ल्स के ट्रायल का आयोजन किया गया। इस ट्रायल में जिले भर से करीब 40 बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों के फिटनेस, स्किल और गेम प्रदर्शन के आधार पर टीमों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ी अब 3 से 5 अप्रैल तक हमीरपुर में आयोजित होने वाली राज्यस्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। टीमों को दो अप्रैल को जिला मुख्यालय नाहन से रवाना किया जाएगा।

निहरी में 10 अप्रैल को होगा 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम

टीम एक्शन इंडिया
खेमचंद शास्त्री

मंडी। उपमंडल सुंदरनगर की ग्राम पंचायत निहरी के मेला मैदान में 10 अप्रैल को 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह करेंगे।

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी की अध्यक्षता में निहरी पंचायत घर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। एसडीएम अमर नेगी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का उनके

घर के नजदीक त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि निहरी सहित आसपास की पंचायतों -घड़ोई, मरहड़ा बदेहन, बजीहन, जरल और बंदली के लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में उपमंडल व जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर व दिव्यांगजन सहायता शिविर आयोजित किया जाएगा, वहीं विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी।

मुख्यातिथि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। एसडीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम से पहले प्राप्त शिकायतों का समाधान कर उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए।

मानगढ़-चनाहलग रूट पर खराब बस को जबरन चलाने का आरोप

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन। राजगढ़ उपमंडल के मानगढ़-चनाहलग-नाहन रूट पर चल रही एकमात्र बस सेवा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि तकनीकी रूप से खराब बस को भी यात्रियों से भरकर सड़क पर दौड़ाया जा रहा है, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश बढ़ गया है और परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार मानगढ़-चनाहलग से नाहन जाने वाली बस के पट्टे (स्प्रिंग) टूटे होने के बावजूद उसे चलाया गया। आरोप है कि इस स्थिति में भी बस को लिंक रोड पर ले जाने के निर्देश दिए गए, जबकि चालक और परिचालक ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बस को केवल मुख्य मार्ग से धीरे-धीरे मुख्यालय तक ले जाने की बात कही थी। उनका तर्क था कि ऐसा

करने से यात्रियों को कम से कम राजगढ़ जाने वाली दूसरी बस मिल जाती और वे सुरक्षित तरीके से आगे का सफर पूरा कर पाते।लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक, कर्मचारियों की बात को नजरअंदाज कर दिया गया और बस को जोखिम भरे हालात में आगे बढ़ाने का दबाव बनाया गया। हालात इतने खराब हो गए कि शिरला के पास यात्रियों को बीच रास्ते में ही उतरना पड़ा। इससे महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि यह रूट पहले ही परिवहन सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि घाटे का हवाला देकर टोन्डा रूट की बस पहले ही बंद की जा चुकी है, और अब मानगढ़-चनाहलग रूट की एकमात्र बस सेवा भी उपेक्षा और अव्यवस्था का शिकार हो रही है। इसका सीधा असर 8 से 9 पंचायतों के लोगों पर पड़ रहा है, जिन्हें रोजमर्रा के काम, इलाज, शिक्षा और सरकारी कार्यों के लिए नाहन पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

चिट्टे के साथ युवक पांवटा में गिरफ्तार

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन। जिला सिरमौर पुलिस ने नशे पर नकेल कसनी के शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पावटा साहिब में एक युवक से करीब साढ़े तीन ग्राम स्नेक (हीरोइन) बरामद की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त संस्था मिली थी कि पावटा साहिब के एक युवक द्वारा नशे की तस्करी की जा रही ह। पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक नशे का आरोपी उत्तराखंड के कुंजा से पैदल ही पांवटा साहिब की ओर आ रहा है , जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोविंदघाट बैरियर पर नाकाबंदी की। इसी दौरान जब बैरियर के पास पांवटा साहिब के देवी नगर का रहने वाला मनु गुप्ता पुत्र सत्य प्रकाश पहुंचा तो पुलिस ने उसके सामान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को व्यक्ति के कैरी बैग से चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक सिरमौर निश्चित सिंह नेगी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी

टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत जिला कांगड़ा ने टीबी उन्मूलन प्रयासों को दी नई गति

धर्मशाला। जिला कांगड़ा में टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समीक्षा-सह-क्षमता निर्माण बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य कार्यक्रम की प्रगति का आकलन, मुख्य परिचालन संकेतकों की समीक्षा, तथा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वयन को और अधिक सुदृढ़ बनाना था। यह बैठक जिला स्तर पर टीबी उन्मूलन प्रयासों को और अधिक गति देने तथा जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी जो टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य की सामूहिक प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। बैठक की अध्यक्षता डॉ. विवेक करोल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा द्वारा की गई। बैठक में डॉ. आर.के. सूद, जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला क्षय रोग अधिकारी, कांगड़ा, डॉ. निकेत, डब्ल्यू एच ओ कंसल्टेंट, तथा जिले के सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स , सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स , ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स तथा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के पर्यवेक्षी स्टाफ उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कार्यक्रम के प्रमुख अधिकारियों और फील्ड स्तर के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी ने टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत चल रही

किशोरियों के लिए गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव को लगेगा एचपीवी टीकाकरण अभियान

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन। जिला सिरमौर में किशोरियों को गंभीर बीमारी से बचाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है। 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की पात्र बालिकाओं के लिए मानव पैपिलोमा विषाणु (एचपीवी) टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले भर में तय तिथियों पर टीकाकरण किया जाएगा। यह अभियान 29 मार्च, 5 अप्रैल, 12 अप्रैल, 19 अप्रैल, 10 मई और 24 मई 2026 को संचालित होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान के लिए जिले के सभी छह चिकित्सा खंडों में तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग की ओर से 19 शीत श्रृंखला केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहां पर्याप्त मात्रा में टीके, आवश्यक लॉजिस्टिक, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी और जागरूकता सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। अभियान के सुचारु संचालन और निगरानी के लिए पर्यवेक्षण टीमें भी तैनात कर दी गई हैं, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे। अभियान के तहत धगेड़ा खंड में मेडिकल कॉलेज नाहन स्थित मातृ-शिशु केंद्र और नागरिक अस्पताल ददाहू को केंद्र बनाया गया है। संगड़ाह खंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संगड़ाह, हरिपुरधार, नोहराधार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटिधिमान को शामिल किया गया है। पांवटा साहिब-राजपुर खंड में नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माजरा, सतौन, कुंडियों, कमरू, गोरखुवाला, जाखना और रामपुर भरापुर को केंद्र बनाया गया है। वहीं शिलाई खंड में नागरिक अस्पताल शिलाई और राजगढ़ खंड में नागरिक अस्पताल राजगढ़ में टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एचपीवी टीका गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव का अत्यंत प्रभावी माध्यम माना जाता है। यह संक्रमण महिलाओं में होने वाले इस गंभीर कैंसर का प्रमुख कारण है। विभाग का कहना है कि यह टीका कम आयु में अधिक प्रभावी रहता है और एकल खुराक के माध्यम से लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। यही कारण है कि इस अभियान को किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभाग ने पात्रता को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केवल वही बालिका टीकाकरण के लिए पात्र होगी जिसकी जन्म तिथि 28 फरवरी 2011 या उसके बाद की हो और टीकाकरण के दिन उसकी आयु 14 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस अभियान के लिए पात्र जन्म तिथि की कुल सीमा 28 फरवरी 2011 से 24 मई 2012 तक निर्धारित की गई है। अभिभावकों से विशेष अपील की गई है कि वे अपनी बेटियों की जन्म तिथि की पुष्टि स्कूल रिकॉर्ड, आधार कार्ड या अन्य आधिकारिक दस्तावेज से अवश्य कर लें, ताकि टीकाकरण के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत न आए।

किसान क्रेडिट कार्ड से कांगड़ा में 1,241 करोड़ रुपये का ऋण वितरित

टीम एक्शन इंडिया

धर्मशाला। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के तहत कांगड़ा जिले में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का व्यापक लाभ मिल रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर ने राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी को संसद में जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक कांगड़ा जिले में 1,04,212 किसान केसीसी के माध्यम से खेती और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना के तहत जिले में कुल 1,241 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है, जिससे किसानों को कृषि कार्यों में आर्थिक सहायता मिली है। मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि कार्यों के लिए 3 लाख रुपये तक तथा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 2 लाख रुपये तक के अल्पकालीन ऋण पर ब्याज में अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2025 से केसीसी धारकों के लिए बिना गारंटी (कोलैटरल-फ्री) ऋण सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। राम नाथ ठाकुर ने यह भी स्पष्ट किया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। ऋण की पात्रता राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तय की जाती है। किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी कुल ऋण राशि का न्यूनतम 18 प्रतिशत कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए आवंटित करें। साथ ही, वर्ष 2016 से इन ऋणों में से 10 प्रतिशत राशि छोटे और मंझोले किसानों को देना अनिवार्य किया गया है।

हिमाचल के बरोटीवाला बैरियर पर एक घंटे चक्का जाम तो गरा मौडा पर प्रदर्शन

टीम एक्शन इंडिया

बरोटीवाला। प्रदेश सरकार द्वारा टोल बैरियरों की दरों में की गई आशातीत वृद्धि पर जहां हर तरफ आलोचना हो रही है वहीं पंजाब के बाद हरियाणा के लोग उबल पड़े हैं। गौरतलब है कि 31 मार्च मध्य रात्रि से नई दरें लागू हो जाएगी। अब आम निजी कार को 70 रुपये की बजाय 170 रुपये लोगों को अदा करने पडेंगे जिससे रोष स्वरुप ज्वाला पूरे पंजाब में भडक़ गई थी। कल जहां नालागढ़ के निकट भरतगढ़ में किसान जत्थेबंदियों व मोर्चों ने दो घंटे चक्का जाम किया था वहीं आज बददी के निकट बरोटीवाला बैरियर पर हरियाणा के गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। लगभग आज बजे के करीब औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला से हिमाचल के वाहनों का आगमन शुरु हुए हरियाणा से पूर्व जिला परिषद चेयरमैन पंचकूला

के नेतृत्व में लोगों ने बैरियर को घेर लिया। उसके बाद हरियाणवी लोगों ने सुक्खू सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाकर चक्का जाम कर दिया। दो घंटे के करीब ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहा। इंडस्ट्रियल एरिया बददी बरोटीवाला झाडमाजरी में हरियाणा से आई कर्मचारियों की बसें भी बरोटीवाला बैरियर पर जाम में फंस गई। इस कारण दर्जनों कंपनियों में रुटीन की शिफट कई घंटे देर से शुरु हुई। हिमाचल पुलिस प्रशासन भी इस बात को लेकर बेबस रहे कि प्रदर्शनकारियों को कैसे शांत करें और जाम कैसे खुलवाएं क्योंकि यह चक्का जाम हरियाणा की सीमा के भीतर हो रहा था। इसके बाद नायब तसहीलदार बददी जगदीश चंद बरोटीवाला बैरियर पर पहुंचे और हरियाणा के लोगों ने उनको लिखित में ज्ञापन सौंपा और टोल बैरियर को अवैध बताकर उसको हटाने की मांग की।

ज्वाली में बैसाखी मेला कमेटी पर उभरा विवाद, पूर्व प्रतिनिधियों ने जताया कड़ा विरोध

टीम एक्शन इंडिया

ज्वाली। जिला स्तरीय बैसाखी मेले को लेकर इस बार विवाद खड़ा हो गया है। मेले के आयोजन के लिए गठित कमेटी का पूर्व पंचायत एवं नगर पंचायत प्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध जताया है। इस संबंध में सोमवार को पूर्व भाजपा पार्षद रवि कुमार, पूर्व पार्षद तिलक रपोत्रा, पूर्व प्रधान डॉ. राजिंदर सिंह और सूरज धीमान सहित अन्य लोगों ने एसडीएम ज्वाली नरेंद्र जरियाल को ज्ञापन सौंपकर आपत्ति दर्ज करवाई। ज्ञापन में प्रतिनिधियों ने कहा कि पहले जब ज्वाली पंचायत थी तो मेले का आयोजन पंचायत प्रधान द्वारा किया जाता था। इसके बाद नगर पंचायत बनने पर यह जिम्मेदारी नगर पंचायत चेयरमैन निभाता रहा। लेकिन वर्तमान में नगर परिषद भंग होने और चेयरमैन न होने की स्थिति में मेले का आयोजन प्रशासन को अपने स्तर पर करना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार जो मेला कमेटी गठित की गई है, उसमें शामिल कुछ लोग आगामी नगर परिषद चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं,

संपादकीय

विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनेगा जेवर एयरपोर्ट

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व विकास योजनाओं के लोकार्पण की लहर चल रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 मार्च को जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) राष्ट्र को समर्पित किया। यह एयरपोर्ट आधुनिकतम सुविधाओं का अद्भुत संगम होगा। यहां से पहली उड़ान उत्तर प्रदेश सरकार के विमान ने भरी, जिसमें प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यात्री बने। इस एयरपोर्ट से चार सप्ताह बाद यात्रियों के लिए नियमित उड़ानें प्रारंभ हो जाएंगी। नोएडा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना का प्रस्ताव 2001 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रखा था किंतु निहित राजनीतिक कारणों से यह अधर में लटका रहा। इस प्रकार इस परियोजना के प्रथम चरण के ही पूर्ण होने में 25 वर्ष लग गए, जिस कारण उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र का विकास भी अटका रहा। जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट के साथ ही विकसित यूपी और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। यूपी अब देश के सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण के पूर्व ही केंद्र सरकार ने उड़ान 2.0 योजना को मंजूरी प्रदान की है जिसके अंतर्गत 100 नए एयरपोर्ट व 200 नये हेलीपैड बनेंगे जिसके लिए 29,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का सपना है कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा का सुगम आनंद ले सकें और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उड़ान 1.0 योजना में 1.6 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की है।प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए सबका प्रयास जरूरी है इस परियोजना के लिए किसानों ने भी अपनी जमीन दी है।आधुनिक कनेक्टिविटी का जो विस्तार हो रहा है उसे पश्चिम यूपी में फूड प्रोसेसिंग को बल मिलेगा और यहां के कृषि उत्पाद दुनिया के बाजारों में और बेहतर तरीके से पहुंच सकेंगे।

जेवर एयरपोर्ट की अहम विशेषताएं: जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा तथा प्रथम चरण में ही यह 1.2 करोड़ यात्रियों को एक रन-वे से सेवा प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह देश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा जो सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा और कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। इस एयरपोर्ट में आगामी चरणों में 5 रन-वे का निर्माण होने के बाद यात्री क्षमता बढ़कर 22.5 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष हो जाएगी। यह एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से चलेगा।

चीनी सीसीटीवी बैन करते थे मुखबिरी?

अजय कुमार

> सरकार का कहना है कि हर कैमरे में एंड टू एंड एनक्रिप्शन, लोकल डेटा स्टोरेज और पारदर्शी सर्वर पॉलिसी होनी चाहिए। डेटा भारत में ही रहेगा। कोई विदेशी सर्वर नहीं। यह बदलाव न सिर्फ जासूसी रोकने के लिए जरूरी है, बल्कि आम नागरिक की निजी जिंदगी की रक्षा के लिए भी है। फिर भी सबसे बड़ा सवाल पुराने कैमरों का है। देश में करोड़ों सीसीटीवी पहले से लगे हुए हैं। इनमें ज्यादातर के पासवर्ड कभी बदले नहीं गए। फर्मवेयर अपडेट नहीं हुए। इंस्टॉलर के पास अभी भी एक्सेस हो सकता है। कई मामलों में घर के कैमरे से ब्लैकमेलिंग के प्रयास भी सामने आए हैं

देश भर में सुरक्षा की दीवार खड़ी करने के नाम पर लगाए जा रहे कैमरे अब खुद सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए थे। लेकिन अब सरकार ने इस चुपके से फैल रही जासूसी के जाल पर सख्ती से हमला बोला है। 1 अप्रैल 2026 से चीनी कंपनियों के इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरों की बिक्री पर रोक लग जाएगी। हिकविजन, दाहुआ और टीपी लिंक जैसे ब्रांड बिना एसटीक्यूसी सर्टिफिकेशन के अब बाजार में नहीं आ सकेंगे। यह फैसला सिर्फ बाजार को बदलने वाला नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा को नई दिशा देने वाला है। हाल की घटनाओं ने साफ कर दिया कि सस्ते कैमरों के पीछे कितना बड़ा खतरा छिपा था।पिछले कुछ हफ्तों में गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसा जासूसी गिरोह पकड़ा, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई सीधे भारतीय रेलवे स्टेशनों की निगरानी कर रही थी। दिल्ली कैंट और सोनीपत स्टेशन के पास सोलर पैनल वाले छिपे कैमरे लगाए गए थे। इनकी लाइव फीड पाकिस्तान तक पहुंच रही थी। अठारह दिन तक सोनीपत स्टेशन के प्लेटफॉर्मों की हर गतिविधि दुश्मन की स्क्रीन पर दिख रही थी। यह सिर्फ एक मामला नहीं था। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे देश में सीसीटीवी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने सभी बड़े शहरों में हर कैमरे की फिजिकल वेरिफिकेशन का आदेश दिया है। क्योंकि पता चला कि कई कैमरे न सिर्फ विदेशी सर्वर से जुड़े थे, बल्कि उनकी फीड बिना किसी की जानकारी के बाहर भेजी जा रही थी। भारत में सीसीटीवी का विस्फोटक विस्तार हुआ है। हर घर के गेट पर, ड्रॉइंग रूम में, बच्चों के कमरे के बाहर, यहां तक कि किचन और बेडरूम तक कैमरे लग रहे हैं। कीमतें गिरने के कारण चीन से सस्ते हार्डवेयर आयात हो रहे थे। भारतीय कंपनियां उन पर अपना स्टिकर चिपका कर बेच रही थीं। लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में कमजोरियां थीं। कैमरा सेटअप करते ही यूजर को कंसेंट देना पड़ता था कि कंपनी रिकॉर्डिंग को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेगी। इसका मतलब साफ था कि आपकी निजी जिंदगी किसी और की स्क्रीन पर भी हो सकती है। डेटा

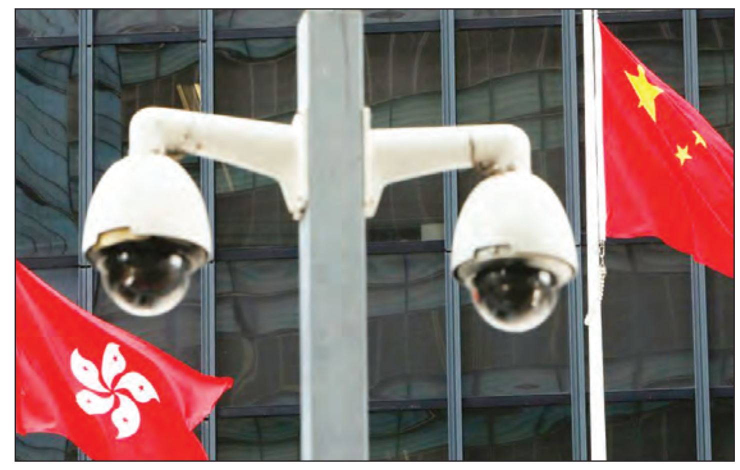

विदेशी सर्वर पर जा रहा था। पासवर्ड डिफॉल्ट रखे जाते थे। इंस्टॉलर सालों तक उसी पासवर्ड से एक्सेस रखता था। फर्मवेयर अपडेट नजरअंदाज कर दिए जाते थे। नतीजा यह कि घर की हर गतिविधि, कब कौन आया, कब बाहर गया, सब किसी और के पास पहुंच जाता था।यह खतरा सिर्फ घरों तक सीमित नहीं था। पब्लिक जगहों पर लगे कैमरे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और भी खतरनाक साबित हो रहे थे। रेलवे स्टेशनों, सरकारी दफ्तरों और संवेदनशील इलाकों में भी यही चीनी कैमरे लगे थे। हाल की जासूसी घटनाओं ने दिखा दिया कि दुश्मन इन्हें आसानी से हाइजैक कर सकता है। मिडिल ईस्ट की हालिया जंग में भी सीसीटीवी को टारगेट बनाकर प्रेसाइज अटैक किए गए थे। भारत में भी यही आशंका थी। इसलिए सरकार ने अब सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। मीटवाई ने सीसीटीवी के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स तय किए हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड, सबकी जांच होगी। बिना सर्टिफिकेशन के कैमरे बेचना गैरकानूनी होगा। यह नियम सरकारी खरीद पर पहले से लागू था, लेकिन अब निजी बाजार पर भी पूरी तरह लागू हो जाएगा। नए नियमों का सबसे बड़ा फायदा भारतीय कंपनियों को मिलेगा। सीपी प्लस, स्पार्श, मैट्रिक्स जैसी देशी ब्रांड्स अब बाजार पर कब्जा कर लेंगी। पहले चीनी ब्रांड्स ने सस्ती कीमत के नाम पर तीस प्रतिशत से ज्यादा बाजार हिस्सा हथिया लिया था। अब कीमतें थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन सुरक्षा की कीमत चुकाने लायक है। सरकार का कहना है कि हर कैमरे में एंड टू एंड एनक्रिप्शन, लोकल डेटा स्टोरेज और पारदर्शी सर्वर पॉलिसी होनी चाहिए। डेटा भारत में ही रहेगा। कोई विदेशी सर्वर नहीं। यह बदलाव न सिर्फ जासूसी रोकने के लिए जरूरी है, बल्कि आम नागरिक की निजी जिंदगी की रक्षा के लिए भी है।फिर भी सबसे बड़ा सवाल पुराने कैमरों का है। देश में करोड़ों सीसीटीवी पहले से लगे हुए हैं। इनमें ज्यादातर के पासवर्ड कभी बदले नहीं गए। फर्मवेयर अपडेट नहीं हुए। इंस्टॉलर के पास अभी भी एक्सेस हो सकता है। कई मामलों में घर के कैमरे से ब्लैकमेलिंग के प्रयास भी सामने आए हैं। कोई आपके घर की रूटीन जान ले तो फिजिकल सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए सरकार को सिर्फ नई बिक्री रोकने से काम नहीं चलेगा। मौजूदा कैमरों का पूरा ऑडिट करना होगा, खासकर पब्लिक प्लेसेज में। हर कैमरे की लोकेशन, मॉडल और सिक्योरिटी चेक हो। आम लोगों को भी जागरूक होना होगा। अगर आप घर में सीसीटीवी लगा रहे हैं, तो कुछ बुनियादी बातें याद रखें। इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद डिफॉल्ट पासवर्ड बदल दें। मजबूत पासवर्ड रखें, जिसमें अक्षर, अंक और स्पेशल कैरेक्टर हों। इंस्टॉलर को कभी भी एडमिन एक्सेस न दें। उसके फोन से लॉगआउट करवाएं। ब्रांड चुनते समय पूछें कि डेटा कहां स्टोर होता है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाले कैमरे चुनें। फर्मवेयर और ऐप नियमित अपडेट करें। अगर संभव हो, तो कैमरे को अलग गेस्ट नेटवर्क पर चलाएं। रिमोट एक्सेस की जरूरत न हो, तो उसे बंद रखें। बेडरूम या निजी जगहों पर कैमरा लगाने से पहले दो बार सोचें। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन गोपनीयता उससे भी ज्यादा।यह फैसला सिर्फ एक ब्रांड पर रोक नहीं है। यह पूरे सिस्टम को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। चीन से आयातित कैमरों में हार्डवेयर बैकडोर की आशंका हमेशा रही है। सॉफ्टवेयर भी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल होता था। अब सरकार सुनिश्चित कर रही है कि हर कैमरा टेस्टेड और सर्टिफाइड हो। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी दे रहे थे कि सस्ते कैमरे सुरक्षा के नाम पर खतरा बन रहे हैं। अब सरकार ने उनकी बात मानी है। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। पुराने कैमरों को अपग्रेड करने या बदलने की मुहिम चलानी होगी। बाजार में पहले से जो स्टॉक है, उसका क्या होगा? कुछ कंपनियां पुराना माल क्लियर करने की तैयारी में हैं, लेकिन एक अप्रैल के बाद बिना सर्टिफिकेशन के बिक्री नहीं होगी। इससे छोटे वेंडरों पर असर पड़ेगा, लेकिन लंबे समय में पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ेगी। भारतीय कंपनियां अब और बेहतर प्रोडक्ट ला रही हैं। वे लोकल सर्वर, बेहतर एन्क्रिप्शन और आसान अपडेट दे रही हैं। आम आदमी को समझना होगा कि सुरक्षा सिर्फ कैमरा लगाने से नहीं आती। उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना और सुरक्षित रखना भी जरूरी है।आज के डिजिटल युग में हर घर और हर सार्वजनिक जगह निगरानी में है। लेकिन निगरानी का मतलब जासूसी नहीं होना चाहिए। सरकार का यह कदम देश को आत्मनिर्भर बनाने और विदेशी खतरे से बचाने का संकेत है। फिर भी जागरूकता सबसे बड़ी सुरक्षा है। हर नागरिक को अपने कैमरे की सेटिंग चेक करनी चाहिए। पासवर्ड बदलना चाहिए। अपडेट करना चाहिए। तभी यह कैमरा सुरक्षा का हथियार बनेगा, न कि कमजोरी। वरना सस्ते कैमरे की चकाचौंध में हम अपनी निजी जिंदगी और राष्ट्र की सुरक्षा दोनों खो सकते हैं। समय आ गया है कि हम सुरक्षा को सिर्फ दिखावा न बनाएं, बल्कि उसे वाकई मजबूत बनाएं।

नई दिल्ली कार्यालय
एक्शन बालाजी हाउस, बी-244, मजलिस पार्क, दिल्ली- 110033

उत्तरी दिल्ली कार्यालय
शक्ति कॉम्पलैक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110042

चंडीगढ़ कार्यालय
फर्स्ट फ्लोर, देश सेवक बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

पंजाब कार्यालय
7/2, थर्ड फ्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

करनाल कार्यालय
224, सेक्टर 32पी, करनाल- 132001

सोनीपत कार्यालय
ऑफिस no. 11, ग्राउंड फ्लोर पवन मेगा मॉल सुभाष चौक सोनीपत

शिमला कार्यालय
किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

ऊना कार्यालय
कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

देहरादून कार्यालय
7/1, बल्लूपुर रोड़, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

साहित्य के सम्मान:लेखनी से ज्यादा लॉबिंग महत्वपूर्ण

विवेक रंजन

सोशल मीडिया के इस दौर में स्थिति यह है कि लेखक बाद में पैदा होता है, सम्मानों की 'फेहरिस्त' पहले तैयार हो जाती है। हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी 'अकादमी' या 'फाउंडेशन' का अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक दूसरे को 'शताब्दी रत्न' घोषित कर चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ये चमचमाती ट्राफियां और शॉल, रचना की साहित्यिक गुणवत्ता की गारंटी हैं? साहित्यिक गुणवत्ता किसी प्रयोगशाला में मापी जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि यह समय की कसौटी पर कसी जाने वाली निरंतरता तथा लेखन की पाठकीय पसंद , एवं उसकी उपयोगिता है। लेकिन वर्तमान समय में 'साहित्यिक गुणवत्ता' और 'पुरस्कार' के बीच का संबंध कुछ वैसा ही हो गया है जैसा राजनीति और नैतिकता का होता है, दोनों साथ दिखते जरूर हैं, पर होते बहुत दूर हैं। आज लेखक की लेखनी से ज्यादा उसकी 'लॉबिंग' महत्वपूर्ण हो गई है। गुणवत्ता घर की खिड़की से झांकती रह जाती है और 'जुगाड़' दरवाजे से अंदर आकर मुख्य अतिथि की कुर्सी संभाल लेता है। ऐसा हर छोटे बड़े पुरस्कार तथा सम्मान में देखने मिल रहा है। सम्मान मिलते ही लेखक को लगने लगता है कि वह अब आलोचना से ऊपर है। यही आत्म-मुग्धता गुणवत्ता के क्षरण का सबसे बड़ा कारण बनती है।

इतिहास गवाह है कि प्रेमचंद को जीते-जी कोई बड़ा सरकारी सम्मान नहीं मिला, पर आज उनके बिना साहित्य अधूरा है। दूसरी ओर, ऐसे सैंकड़ों 'पुरस्कार प्राप्त' लेखक हैं जिनकी किताबें आज कबाड़ के भाव भी कोई नहीं पढ़ना चाहता। साहित्यिक गुणवत्ता का अंतसंर्बंध पुरस्कारों से केवल तब ही सार्थक है, जब पुरस्कार 'सृजन' का परिणाम हो, न कि 'अभियान' का। जब किसी योग्य रचना को सम्मानित किया जाता है, तो सम्मान की गरिमा बढ़ती है, रचना की नहीं। ऐसे पुरस्कार में विवाद नहीं होते । रचना तो अपनी गुणवत्ता के कारण पहले ही कालजयी हो चुकी होती है।

समकालीन विडंबना इसके विपरीत इसलिए है, क्योंकि गुण धर्मियों की उपेक्षा कर लॉबी जनित राजनैतिक प्रभाव से पुरस्कार तय हो रहे हैं। आज के दौर में 'सम्मान वापसी' से लेकर 'सम्मान पाने की होड़' तक, साहित्य का बाजारवाद हावी है। गुणवत्ता कहीं हाशिए पर खड़ी इस बात का इंतजार कर रही है कि काश कोई पाठक बिना किसी 'प्रशस्ति पत्र' को देखे किताब के पन्ने पलटे।"सच तो यह है कि असली पुरस्कार पाठक की वह आँखें हैं, जो आधी रात को आपकी किताब पढ़ते हुए नम हो जाती हैं। बाकी सब तो ड्राइंग रूम की धूल झाड़ने वाली निर्जीव वस्तुएं हैं।" पुरस्कार और गुणवत्ता का अंतसंर्बंध तब तक ही पवित्र है जब तक चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और रचना में ईमानदारी है।

विचार

श्चिमी यूपी में मायावती पुराने सपने और नई रणनीति के साथ

संजय सक्सेना

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के उद्घाटन के बहाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य और उसके लिए हाईकोर्ट की अलग बेंच बनाने की मांग फिर से उठाना केवल एक भावुक नारा नहीं है, बल्कि एक लंबी चली आ रही राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इस मुद्दे को बार-बार तराशकर वह न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्थानीय असंतोष को अपनी राजनीति में बदलना चाहती हैं, बल्कि बसपा को एक वैकल्पिक अस्तित्व के रूप में भी स्थापित करना चाहती हैं, जिससे दल को ताकत और मान्यता दोनों मिल सकें। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होते ही मायावती ने यह दावा किया कि इस परियोजना की रूपरेखा और इसके जरूरी बुनियादी काम उनकी बसपा सरकार के शासनकाल में ही शुरू हो चुके थे। उनका यह दावा बसपा को विकासवादी दल के रूप में पेश करने वाला है, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने यह संदेश जाता है कि बसपा केवल जातिगत मुद्दे उठाने वाली पार्टी नहीं, बल्कि बड़ी परियोजनाओं की सोच भी रखती है। इस तरह वह एयरपोर्ट के नाम पर न केवल अपने शासनकाल की राजनीतिक विरासत जीवित रख रही हैं, बल्कि मौजूदा सरकार और अन्य तीनों बड़े दलोंकृभाजपा, सपा और कांग्रेसकृको विकास कार्यों में देरी और रुकावट का दोषी भी ठहरा रही हैं। इसी कड़ी में वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की अलग बेंच और वहाँ के लिए अलग राज्य बनाने के सपने को दोहरा कर एक नया तर्क बना रही हैं। उनका संदेश स्पष्ट है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो औद्योगिक गलियारों, खजूरी खेतों, और नोएडाद्दगुरुग्राम जैसे नए शहरों का घर है, आज भी अदालती और प्रशासनिक देरी और निर्णयों की दूरी से जूझ रहा है। इस असंतोष को वह बसपा के पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वहाँ के छोटे व्यापारी, उद्योगपति, भूमि-मालिक और नव-निर्मित पड़ोस बसपा को अपनी उम्मीद का केंद्र बना सकें, जो पहले शायद भाजपा या सपा की ओर झुके रहे हैं। अलग प्रदेश की मांग को फिर से उठाकर मायावती बसपा के लिए कई तरह के फायदे तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले, यह मुद्दा पार्टी को एक बड़े राज्य-स्तरीय रणनीति के रूप में पेश करता है, न कि केवल जातिगत या विधानसभा-स्तरीय तंत्र के रूप में। उत्तर प्रदेश के विभाजन की चर्चा आज-कल केवल बसपा तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य भर के राजनीतिक गलियारों में भी चल रही है, लेकिन बसपा इसे अपनी राजनीति का केंद्र बनाकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखना चाहती है। इससे पार्टी को एक नई राजनीतिक भाषा भी मिलती है, जिसमें न केवल दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों की बात होगी, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास और न्याय की बात भी शामिल होगी। दूसरे, अलग प्रदेश की मांग बसपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जातिगत और सामाजिक समूहों को एक साथ जोड़ने का मौका देती है। यहाँ दलित, ओबीसी, जाट, गुज्जर, राजपूत और अन्य छोटी जातियाँ रहती हैं, जो अक्सर अलग-अलग राजनीतिक दलों के खेमों में बंटी रहती हैं। मायावती की रणनीति यह है कि स्थानीय असंतोष और विकास की मांग को एक दूसरे से जोड़कर बसपा उन सबको एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करे, जहाँ जाति अलग-अलग नहीं होगी, बल्कि क्षेत्रीय और विकासवादी एजेंडा हावी होगा। ऐसी स्थिति में बसपा न केवल अपनी मूल आधार-जनता को बचाए रख सकती है, बल्कि नए वोट-बैंक भी बना सकती है, जो पहले भाजपा या सपा के पास रहते थे। तीसरा, यह रणनीति बसपा को राजनीतिक रूप से ह्लमजबूत विपक्षी दलह्व के रूप में दिखाने में मदद कर सकती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा-संचालित राज्य सरकार के दौर में अलग राज्य की मांग से यह संदेश निकलता है कि प्रदेश बड़ा होने के कारण विकास और न्याय दोनों ही धीमे हो रहे हैं। इस दावे को बसपा अपने विकासवादी एजेंडा के साथ जोड़कर यह बताना चाहती है कि अगर वह सत्ता में आई, तो सिर्फ जातिगत आरक्षण और सामाजिक न्याय तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रशासनिक सुधार और भू-राजनीति को भी नए सिरे से सोचेगी।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआई: HPHIN / 2012 / 48072

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन इंडिया कार्यालय, कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना हिमाचल प्रदेश–174303 से प्रकाशित एवं अर्थ प्रकाश प्रैस, अर्थ प्रकाश भवन, सेक्टर–29डी, चंडीगढ़ से मुद्रित।

संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी

समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)

स्थानीय संपादक : पंकज शर्मा (9418026789)

ई-मेल : actionindiashimla@gmail.com
actionindiauna@gmail.com

एक्शन इंडिया शिमला कार्यालय: किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला– 171001

एक्शन इंडिया ऊना कार्यालय: कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना, हिमाचल प्रदेश–174303

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच–पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

आलेख

सबकी जिम्मेदारी अब सचमुच सबकी

कृति आरके जैन

सुबह की रसोई में उबलती चाय की भाप के साथ एक और चीज उठ रही है–खामोश विद्रोह। यह विद्रोह दरवाजे पटककर नहीं, बल्कि दरवाजे धीरे से बंद करके होता है। महिलाएँ अब घर छोड़ नहीं रहीं, नौकरी छोड़ नहीं रहीं, पर ह्लसब कुछ संभालनेह्व की अदृश्य जिम्मेदारी से पीछे हट रही हैं। इसे ही घर से ह्यक्वाइट क्विटिंगह्व कहा जा रहा है। यह लापरवाही नहीं, आत्मरक्षा है; असंवेदनशीलता नहीं, संतुलन की माँग है। दशकों से घर की दीवारों में कैद वह मानसिक बोझ, जिसे कर्तव्य कहकर सामान्य बना दिया गया था, अब प्रश्नों के कटघरे में है। यह नई लहर बिना नारों के, बिना मंचों के, सीधे रसोई और बैठक के बीच जन्म ले रही है। क्वाइट क्विटिंग शब्द कार्यस्थल से आया, पर घर के भीतर इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है। दफ्तर में कर्मचारी अतिरिक्त काम छोड़ता है, यहाँ महिला अतिरिक्त भावनात्मक और संज्ञानात्मक श्रम छोड़ रही है। मेंटल लोड वह अदृश्य सूची है जो उसके दिमाग में हर समय चलती रहती है–बच्चों की परियोजना, सास की दवा, पति की मीटिंग, त्योहार की तैयारी, रिश्तों की मरम्मत। समय उपयोग सर्वेक्षण 2024 के आँकड़े बताते हैं कि भारतीय महिलाएँ प्रतिदिन पुरुषों से कई घंटे अधिक अवैतनिक श्रम करती हैं। महिलाएँ रोजाना 289 मिनट अनपेड घरेलू कामों पर और 137 मिनट देखभाल पर खर्च करती हैं जबकि पुरुष केवल 88 और 75 मिनट। यह सिर्फ समय नहीं, ऊर्जा और पहचान की कीमत भी है। यही असमानता अब प्रतिरोध को जन्म दे रही है। महामारी ने इस असंतुलन को निर्वस्त्र कर दिया। घर ही दफ्तर बना, दफ्तर ही घर, और महिला दोनों की प्रबंधक। लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे वह मीटिंग में थी, और कैमरे के बाहर रसोई में। इसी दौर में सोशल मीडिया ने वैश्विक संवाद खोला। हजारों भारतीय महिलाएँ लिखने लगीं कि वे परफेक्ट होने की दौड़ से बाहर निकलना चाहती हैं। नई पीढ़ी की मिलेनियल और जेन-जेड महिलाएँ अपनी माताओं की थकान को विरासत नहीं बनाना चाहतीं। वे समझ चुकी हैं कि त्याग का अनंत महिमामंडन असल में असमानता को स्थायी बनाता है।

शादी में डी. जे. का एडवेंचर

चँगू जी ने मँगू जी से कहा। भाई सुना है तुम्हारे यहाँ शादी है। हाँ ठीक सुना है , भाई। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। भाई तुम्हारे यहाँ शादी है इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्यों कोई खास बात। नहीं भाई ऐसे ही। वो बात ये है कि तुम्हारे यहाँ तो डी. जे. भी बजेगा। हाँ , शादी है तो डी. जे. भी बजेगा और नाच- गाना भी होगा। क्यों पूछ रहे हो। अरे नहीं भाई मेरे भाई की तबीयत डी. जे. से बहुत घबराती है। सोच रहा था कि अगर डी. जे. ना बजता तो ठीक रहता। लेकिन शादी में शोर ना हो तो मजा नहीं आता। आखिर शादी- ब्याह, संगीत और शोर के लिए ही तो होता है। जब शोर ना हो। हो -हल्ला ना हो तो क्या फायदा ऐसी शादी का। और तो और मैंने तो डी. जे. वाले को एडवांस पैसा भी दे रखा है। मेरा एडवांस पैसा बर्बाद हो जाएगा। भाई चँगू जी डी. जे. का पैसा मुझसे ले लेना। चँगू जी ने मँगू जी से वीनित भाव से कहा। मँगू जी बोले भाई मैं घर में पूछ कर बताता हूँ। ठीक है भाई। मँगू ने घर में ये समस्या बताई कि चँगू जी के भाई दिल के मरीज हैं। लिहाजा डी. जे नहीं बजेगा। वैसे तो डी. जे. का बजना या नहीं बजना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हमारे समाज में एक -से -इक्कीस लोग होते हैं। जो किसी भी बात को ना होना। अपनी नाक का कटना मानकर चलते हैं। उनकी नाक हर छोटी -बड़ी बात पर कट जाती है। मँगू के भाई सँगू के लड़के तँगू की शादी थी। एक रिश्तेदार ने कहा कि आपका तो एक ही लड़का है। क्या आप उसकी शादी बार -बार कीजियेगा। दिल के अरमान दिल में रह जाते हैं। आखिर किसी के कहने से डी. जे. ना बजेगा। आखिर समाज में हमारी भी तो कोई इज्जत है। सब ने हाँ -में -हाँ मिलाई। ऐसे समय में लोग मजे ले लेकर बात को हवा देते हैं।

बिना झँझट के शादी हो जाए। ऐसा होना ठीक नहीं रहता है। सबको कुछ ना कुछ एडवेंचर चाहिए होता है। चर्चा आगे बढ़ी। एक ही शादी है। वो भी सालों बाद इस घर में हो रही है। डी. जे.के बिना फीका-फीका नहीं लगेगा। इतनी लाईट ,इतना डेकोरेशन सब जाया जाएगा। इस छोटी सी बात को बड़ा बनाया गया। तुरंत- फुरंत में बैठक बुलाई गई।

देश-दुनिया के सभी निवेशकों के लिए खुले हैं मध्य प्रदेश के दरवाजे: डॉ. मोहन यादव

अनुदान राशि

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्टार्टअप को लगभग 28 लाख से अधिक की अनुदान राशि की प्रथम किश्त भी जारी की

टीम एक्शन इंडिया

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही है। देश-दुनिया के सभी निवेशकों के लिए प्रदेश के दरवाजे खुले हैं। हम उद्योग मित्र नीतियों और सहयोग की भावना के साथ उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को समर्थ एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश की थीम पर भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में प्रदेश की 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को उनके खाते में 169.57 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से जारी की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्टार्टअप को लगभग 28 लाख से अधिक की अनुदान राशि की प्रथम किश्त भी जारी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने लघु उद्योग निगम की ओर से आठ करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का चैक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने बैतूल और आगर-मालवा के तीन उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के लिए आवंटन-पत्र प्रदान किए और मुख्यमत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत हितलाभ वितरण भी किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक सशक्त, आर्थिक रूप से सुदृढ़ और बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले प्रथम तीन राज्यों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग हो या कृषि, हर क्षेत्र में योगदान के लिए निरंतर सक्रिय है। एमएसएमई इकाइयां औद्योगिक गतिविधियों का प्रभावी केन्द्र होने के साथ लाखों परिवारों के स्वावलंबन का आधार भी है। उन्होंने कहा कि आज का आयोजन महावीर जयंती के शुभ अवसर पर हो रहा है। यह भगवान महावीर के जनकल्याण और शुचिता के सिद्धांतों को साकार करने का भी प्रतीक है। प्रदेश में उद्योग-व्यापार गतिविधि और उद्यमिता प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करते हुए निरंतर नवाचार जारी हैं। राज्य सरकार उद्यमियों को लिए पूंजी, भूमि और व्यवस्थाओं में सरलता कर, उनकी प्रगति की राह को आसान बना रही है। विभाग द्वारा बड़ी राशि का सिंगल क्लिक से सीधे अंतरण व्यवस्था में सुगमता और स्पष्टता का परिचायक है। पूरे देश में मार्च क्लोजिंग का वातावरण है, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई इकाइयों और उद्यमियों को राशि और सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह प्रदेश में नए संकल्पों के साथ नया वित्तीय वर्ष आरंभ करने का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही भारत स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर है। युद्ध के दोनों पक्ष भारत का सहयोग कर रहे हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी की कुशल नीतियों से ही संभव है। जहां एक ओर विश्व के कई देशों में पेट्रोल-डीजल, गैस की उपलब्धता प्रभावित हो रही है, वहीं हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी ने इनके मूल्यों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत समर्थ भी है और सक्षम भी।

सभी क्षेत्रों में हो रही है प्रगति : मंत्री काश्यप

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव जनता के बीच सक्रिय होने के साथ प्रशासनिक दृष्टि से भी निरंतर गतिशील हैं। उनके व्यापक और स्पष्ट दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप प्रदेश उद्योग-व्यापार, कृषि, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने सहित सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। प्रमुख सचिव राघवेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में विभाग में डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महावीर जयंती पर श्रमण मुनि श्री 108 संभव सागर महाराज का लिया आशीर्वाद

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महावीर जयंती पर श्रमण मुनि श्री 108 संभव सागर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को भोपाल के दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन समाज द्वारा संयुक्त तत्वावधान में निकाली जा रही भगवान महावीर स्वामी की शोभायात्रा का इतवारा पहुंचकर स्वागत कर यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुनि श्री 108 संभव सागर महाराज सहित अन्य मुनिगण को श्रीफल भेंट कर

उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, दिगम्बर पंचायत कमेटी के अध्यक्ष पंकज जैन, सुपारी और श्वेताम्बर समाज के अध्यक्ष राजेश तांतेड़ उपस्थित थे।

राम जन्मभूमि के हनुमान मंदिर में 2 अप्रैल को होगा ध्वजारोहण।

भगवान महावीर जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा

प्रयागराज। भगवान महावीर जयंती के शुभ अवसर पर सोमवार को जैन मंदिर से रथ शोभा यात्रा निकाली गई। रथ में वर्धमान के माता-पिता विराजमान थे। जिनकी आरती उतार कर यात्रा प्रारम्भ की गई। लोगों के हाथों में धार्मिक ध्वज पताका थे, ढोल ताशा पार्टी, डीजे, पंजाबी बैंड, अनेक झांकियां, ऐरावत हाथी, गाते बजाते नृत्य करते देव-देवियां तथा बग्घी में वर्धमान के माता-पिता लोगों को दर्शन दे रहे थे। सड़क के दोनों ओर श्रद्धालु हाथ जोड़कर दर्शन कर रहे थे फूलो की वर्षा करके रथ यात्रा का स्वागत किया जा रहा था। महिलाएं और बच्चे पीले रंग का वस्त्र पहने हुए थे ऐसा लग रहा था जैसे सरसों का फूल लहरा रहे है। सभी जयकारे लगाकर थिरक रहे थे। भक्त भगवान महावीर के संदेशों को लोगों तक पहुंचा रहे थे।

मुख्यमंत्री ने 1.22 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यूनिफॉर्म के लिए दी राशि

चेक वितरित

मुख्यमंत्री ने लाडो प्रोत्साहन योजना और कालीबाई भील योजना के लाभार्थियों को भी चेक वितरित किए

टीम एक्शन इंडिया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की एक लाख 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को दो यूनिफॉर्म के लिए एक-एक हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना और कालीबाई भील योजना के लाभार्थियों को भी चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नौनिहालों की देखभाल कर भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रही हैं और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और अन्य मानदेय कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया है, जो एक अप्रैल 2026 से लागू होगा। साथ ही अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में पांच दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और मरम्मत के कार्य भी तेजी से कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकताओं और महिला पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं तथा भविष्य में उनकी आंखों की निःशुल्क जांच और चश्मा उपलब्ध कराने की योजना भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए राज्य में 19 मार्च से 15 मई तक मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गांवों और शहरी वार्डों के समग्र विकास के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

बिहार की राजनीति के 'शिखर पुरुष' नीतीश कुमार का सफरनामा

पद से इस्तीफा

विधान परिषद की सदस्यता छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया

टीम एक्शन इंडिया

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार पहली बार 2006 में विधान परिषद के सदस्य बने थे। उसके बाद 2012, 2018 और 2024 में लगातार चौथी बार उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली । विधान परिषद की सदस्यता छह वर्ष के लिए होती है। उनके टर्म इस प्रकार रहे- 2006-2012, 2012-2018, 2018-2024 और 2024 से अब तक। साल 2005 के नवंबर में पहली बार बिहार की सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने हमेशा विधान परिषद के रास्ते मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

उन्होंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। 1985 में हरनौत से विधायक चुने जाने के बाद वे लोकसभा सदस्य भी रहे और केंद्र में मंत्री पद भी संभाला। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधानसभा की बजाय विधान परिषद की सदस्यता को प्राथमिकता दी। राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार अब चारों सदनों के सदस्य बन जाएंगे। उन्होंने पहले विधानसभा (विधायक), फिर लोकसभा (सांसद), उसके बाद विधान परिषद और अब राज्यसभा की सदस्यता हासिल कर ली है। यह उनके राजनीतिक करियर में एक अनोखा उपलब्धि मानी जा रही है। विधान परिषद की सदस्यता छोड़ने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना होगा।

समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

टीम एक्शन इंडिया

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। सभी के प्रार्थना पत्र लिए और अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित की उचित समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है।

मंदिर पर कब्जे की शिकायतः

उन्नाव के बांगरमऊ से आईं ममता तिवारी ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देते हुए कुछ लोगों पर मंदिर

कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कब्जा करने वाले लोग मंदिर में पूजा भी नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। बदायूं से आए एक किसान ने बताया कि कुछ लोगों ने उनकी फसल नष्ट कर दी और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बलरामपुर जिले से आए एक फरियादी ने बताया कि गांव की सड़क बहुत खराब है।

ग्राम प्रधान कई वर्षों से इसका निर्माण नहीं होने दे रहे हैं, जिससे आवागमन में काफी परेशानी होती है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव में जाकर ग्रामीणों से बातचीत करें। स्थिति का खुद आकलन करें और सड़क निर्माण कराएं।

मुख्यमंत्री ने डॉ. जितेन ठाकुर को उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किया सम्मानित

टीम एक्शन इंडिया

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड भाषा संस्थान के उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह 2025 में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 'उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान' से डॉ. जितेन ठाकुर को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र, श्याम सिंह कुटौला, डॉ. प्रीतम सिंह, केसर सिंह राय तथा अताए साबिर अफजल मंगलौरी को 'उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट साहित्यकारों एवं 'युवा कलमकार प्रतियोगिता' के विजेताओं को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने साहित्य नारी वंदन सम्मान के अंतर्गत प्रो. दिवा भट्ट, उत्कृष्ट बाल साहित्य के लिए प्रो. दिनेश चमोला, उत्तराखंड मौलिक रचना पुरस्कार के लिए डॉ भूपेंद्र बिष्ट, डॉ सुधा जुगरान, शीशपाल गुसाई, उत्कृष्ट कुमाऊंनी और गढ़वाली साहित्य में तारा पाठक, हेमंत सिंह बिष्ट और गजेंद्र नौटियाल आदि को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह अत्यंत गर्व का विषय है कि उन्हें प्रदेश के महान साहित्यकारों

को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि 'उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान' से सम्मानित डॉ. जितेन ठाकुर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे हिंदी साहित्य जगत के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं। उन्होंने सभी सम्मानित साहित्यकारों को बधाई देते हुए कहा कि वे अपनी रचनात्मकता के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत को समृद्ध करने के साथ नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। धामी ने कहा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह प्रदेश की साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और साहित्यकारों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पावन भूमि सदियों से ज्ञान, संस्कृति और सृजन का केंद्र रही है, जहां हिमालय, गंगा और प्राकृतिक सौंदर्य ने अनेक लेखकों और कवियों को प्रेरित किया है। सुमित्रानंदन पंत, गौरा पंत 'शिवानी', मोहन उप्रेती और शैलेश मटियानी जैसे साहित्यकारों ने इस धरा को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और लेखक केवल शब्दों के निमार्ता नहीं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक और प्रेरक भी होते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तराखंड राज्य निर्माण में साहित्यकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न पुरस्कारों के माध्यम से साहित्यकारों को सम्मानित करने के साथ-साथ ग्रंथ प्रकाशन के लिए अनुदान भी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य में दो 'साहित्य ग्राम' स्थापित किए जा रहे हैं, जहां साहित्यकारों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

कायस्थ समाज का देश-प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान : मुख्यमंत्री

टीम एक्शन इंडिया

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सोमवार को चंदखुरी में कायस्थ मंगल भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कायस्थ समाज को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माता कौशल्या की पावन भूमि चंदखुरी में इस मंगल भवन का शुभारंभ होना पूरे समाज के लिए खुशी और गौरव का विषय है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कायस्थ समाज सदैव से एक प्रबुद्ध और जागरूक समाज रहा है, जिसने देश एवं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन से लेकर सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस समाज की सक्रिय भूमिका रही है, जो प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए

विजन डॉक्यूमेंट में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और उन्हें विश्वास है कि कायस्थ समाज इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन इस बात का प्रतीक है कि जब समाज संगठित होकर कार्य करता है, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर प्रदेश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो रहे विस्तार का उल्लेख करते हुए बताया कि आज अंबिकापुर से दिल्ली और कलकत्ता के लिए सीधी हवाई सेवा प्रारंभ की गई है, जिससे प्रदेशवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने बजट में सीजी वायु योजना का प्रावधान किया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। साथ ही कार्गो सेवा भी प्रारंभ की गई है, जिससे किसान अपने उत्पाद राष्ट्रीय एवं

भूमिका

शासन-प्रशासन से लेकर सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इस समाज की सक्रिय भूमिका रही है: सीएम

अंतरराष्ट्रीय बाजार तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। इस अवसर पर नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ मंगल भवन का निर्माण समाज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि यह भवन किसी एक समाज के लिए नहीं, बल्कि सर्व समाज के उपयोग के लिए बनाया गया है। यहां सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह भवन आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा और क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वी.वाय. हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. पूर्णेंदु सक्सेना ने कहा कि इस मंगल भवन का निर्माण पूरे समाज के सहयोग से संभव हुआ है और इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं।

उन्होंने कहा कि माता कौशल्या की पावन भूमि पर इस भवन का निर्माण होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और यह भवन निश्चित रूप से शुभ कार्यों में उपयोगी सिद्ध होगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, सहित कायस्थ समाज के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

प्रशासन में ऐसा विभाजन पहले कभी नहीं देखा: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

टीम एक्शन इंडिया

पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम बंगाल में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर लगातार हो रहे तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नारायणगढ़ की चुनावी सभा से तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन में इस तरह की भागीदारी और विभाजन पहले कभी नहीं देखा गया। सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य के कई अनुभवी अधिकारियों को हटाया जा रहा है और प्रशासन को विभाजित किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह देखा जा रहा है कि कौन अधिकारी आरएसएस या भाजपा से जुड़ा है।

कदमों का उल्टा असर पड़ेगा और जनता इसका जवाब वोट के माध्यम से देगी। मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर भी सवाल उठाया। सुनियोजित साजिश के तहत आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।

हालांकि उन्होंने कहा कि इससे चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाल ही में कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पेश किए गए चार्जशीट पर भी ममता बनर्जी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट निकलनी चाहिए। सभा में उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया।

facebook.com/actionindialive twitter.com/actionindianews youtube.com/actionindiatv

हिमाचल न्यूज
एक्शन इंडिया
www.actionindialive.com

ऊना,
31 मार्च 2026

एचपीयू कार्यप्रणाली : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 186 नियुक्तियों पर गंभीर आपत्तियां

खामियां

» हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और शैक्षणिक व्यवस्था में गंभीर खामियां

पंकज शर्मा

शिमला। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की ताजा अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और शैक्षणिक व्यवस्था में गंभीर खामियां सामने आई हैं। मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए तैयार यह रिपोर्ट 30 मार्च, 2026 को विधानसभा में पेश की गई।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020–23 के दौरान विश्वविद्यालय में 27 से 37 प्रतिशत तक संकाय पद खाली रहे जिससे शिक्षण गुणवत्ता प्रभावित हुई और छात्रों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर 186 नियुक्तियों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खडें किए हैं हैरानी की बात यह है कि पूर्व में भी इस कमी को रेखांकित किया गया था, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय में संसाधनों की कमी, कमजोर बुनियादी ढांचा, शोध गतिविधियों में गिरावट और प्रशासनिक खामियों के कारण विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। कैग ने इन कमियों को दूर करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई है।

नियुक्तियों में भी अनियमितताएं

रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय ने एक अयोग्य सहायक प्राध्यापक और एक अतिथि संकाय की नियुक्ति कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का उल्लंघन किया। साथ ही 186 नियुक्तियों में दस्तावेजों का सत्यापन तक नहीं कराया गया।

1.99 करोड़ की लागत से खरीदे उपकरण बने शो पीस

बुनियादी ढांचे की स्थिति भी चिंताजनक पाई गई है। केवल 51 प्रतिशत कक्षाएं ही आईसीटी-सक्षम थीं और विज्ञान प्रयोगशालाओं में 36 से 79 प्रतिशत तक उपकरणों की कमी रही। करीब 1.99 करोड़ के महंगे वैज्ञानिक उपकरण वर्षों से खराब पड़े हैं। वहीं 11.19 करोड़ की लागत से बना इआरपी सिस्टम भी लगभग पूरी तरह निष्क्रिय रहा।

पाठ्यक्रम भी नहीं किए अपडेट

शैक्षणिक स्तर पर भी गंभीर खामियां उजागर हुईं। कई पाठ्यक्रम वर्षों तक अपडेट नहीं किए गए और अधिकांश मामलों में बिना छात्रों या शिक्षकों की राय लिए बदलाव किए गए। अध्ययन बोर्डों के गठन में भी देरी और प्रतिनिधित्व की कमी देखी गई। अनुसंधान के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय पिछड़ा हुआ पाया गया। तीन वर्षों में प्रति शिक्षक औसतन केवल 0.1 शोध परियोजना शुरू हुई, जो मानकों से काफी कम है।

बंगाणा-तूतड़ू सड़क निर्माण में 12 करोड़ खर्च पर उठे सवाल, जांच की उठी मांग

राजन पुरी

ऊना। कुटलैहड़ कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राम आसरा शर्मा ने बंगाणा से तूतड़ू सड़क निर्माण कार्य को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। शर्मा ने बंगाणा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्ष 2020–21 में लगभग 12 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर इस सड़क का चौड़ा व तारकोल से पक्का करने का कार्य किया गया था, लेकिन एक ही वर्षों में सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि जनता के पैसों से बनने वाली सड़कों में यदि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह न केवल धन की बर्बादी है बल्कि आम लोगों के साथ अन्याय भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस ठेकेदार ने इस सड़क का निर्माण किया, उसने गुणवत्ता के मानकों का सही पालन नहीं किया, जिसके कारण सड़क समय से पहले ही टूटने लगी।

गाद व खनन से प्रभावित मछुआरों की आजीविका, सरकार ने अतिरिक्त सहायता की घोषणा

प्रभाव

» मछुआरों की आजीविका पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव की पैरवी

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मछुआरों की समस्याओं का मुद्दा प्रमुखता से उठा। विधायक कमलेश ठाकुर ने नदियों में बढ़ती गाद और अन्य कारणों से मछुआरों की आजीविका पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव तथा अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के कारण मछुआरों की आय पर सीधा असर पड़ रहा है।

उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि जहां रेत की मात्रा अधिक है, वहां नियमानुसार खनन किया जा रहा है और मछुआरों के हित में विभिन्न योजनाएं लागू हैं।

उन्होंने घोषणा की कि मछुआरों को दो माह तक 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों की मैपिंग खनन विभाग और वन विभाग के समन्वय से कराई जाएगी, ताकि व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसायटी के गठन के सुझाव पर भी सकारात्मक विचार किया जाएगा तथा नदियों से गाद हटाने के प्रयास निरंतर जारी हैं।

चर्चा के दौरान विधायक भवानी सिंह पठानिया ने उपायुक्त के माध्यम से मानचित्र तैयार करवाने का सुझाव दिया। विधायक जीत राम कटवाल ने कोऑपरेटिव सोसायटी के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि विधायक इंद्र सिंह गांधी ने अपने क्षेत्र में गाद की समस्या और मृत मछलियों के मिलने का मुद्दा उठाया।

गाद और खनन की बढ़ती समस्या मछुआरों की आजीविका पर गहरा प्रभाव डाल रही है। इसे देखते हुए सरकार राहत, योजनाओं और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से समाधान की दिशा में कार्य कर रही है।

साधुओं को लंगर छकाया, गुरु घर की रीत को किया ताजा

राजन पुरी

ऊना। श्री गुरु नानक देव जी के वंशज व ऊना नगर के संस्थापक बाबा साहिब सिंह बेदी के जन्म दिवस के अवसर पर सोमवार को गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई साधुओं को लंगर करवाने की प्रथा को ताजा किया गया। वर्तमान समय ऊना में गुरु नानक देव जी के वंशजों के गृह अस्थान किला बाबा साहिब सिंह बेदी में गुरु नानक देव जी की 17वीं पीढ़ी बाबा सरबजोत सिंह बेदी द्वारा साधुओं के लिए लंगर का आयोजन किया गया। गुरु नानक देव जी के बड़े सपुत्र बाबा श्री चंद्र महाराज द्वारा चलाए गए उदासीन मत से संबंधित उदासी साधुओं व अन्य अखाड़ों व डेरों से सबंधित सैंकड़ो साधुओं द्वारा इस अवसर पर भोजन दिया गया। इस अवसर पर बाबा अमरजोत सिंह बेदी व बाबा तेगवीर सिंह बेदी द्वारा विभिन्न अखाड़ों से आए साधुओं को सम्मानित किया गया।

ब्रांच चंबी नेरवा में रक्तदान शिविर का आयोजन

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन के तत्वावधान में संत निरंकारी मंडल की ब्रांच चंबी चौपाल द्वारा कंवर कॉम्प्लेक्स नेरवा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें निरंकारी भक्तों व स्थानीय लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर राक्तदान की निस्वार्थ सेवा में योगदान दिया गया।

इस शिविर में आईजीएमसी शिमला हॉस्पिटल के ब्लड बैंक विभाग से सम्मिलित डॉक्टर सुधीर तथा उनकी टीम ने लगभग 70 यूनिट रक्त एकत्रित किया। रक्तदान शिविर में मुख्य उपस्थिति आदरणीय श्री हेमराज भारद्वाज (संयोजक शिमला) की रही। इस उपलक्ष्य पर सेवानिवृत्ति तहसीलदार ओम प्रकाश मेहता जी भी मौजूद रहे।

सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं का अमर संदेश देकर रक्तदान को मिशन की आध्यात्मिक सेवा का अभिन्न अंग बना दिया। यह संदेश आज भी प्रत्येक निरंकारी भक्तों के हृदय में सेवा और समर्पण की प्रेरक लौ बनकर जीवंत है।

यह महाअभियान केवल रक्तदान नहीं, बल्कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की दिव्य सिखलाईयों करुणा, सेवा और एकत्व जैसे मानवीय मूल्यों को जीवन में उतारने का सजीव माध्यम है जो हमें यह सिखाता है कि मानवता ही सर्वोच्च धर्म है। इसी प्रेरणा से प्रेरित संत निरंकारी मिशन, सेवा और समर्पण के पथ पर निरंतर मानवता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

घड़ों में सांसद मोबाइल टीम ने जांचे 40 मरीजों का स्वास्थ्य

राजन पुरी

ऊना। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घड़ों गांव में सोमवार को सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।

दोपहर बाद तक चले शिविर में कुल 40 ग्रामीणों का नि:शुल्क स्वास्थ्य जांचा। इस दौरान ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और हीमोग्लोबिन जैसी महत्वपूर्ण जांचें भी मुफ्त में उपलब्ध करवाई गईं। इन सुविधाओं के कारण ग्रामीणों को अपने ही गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकीं और उन्हें अस्पतालों के चक्कर लगाने से भी राहत मिली। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. अंशु शर्मा ने मरीजों की विस्तृत जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया।

जरूरतमंद लोगों को मौके पर ही निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। शिविर के सफल आयोजन में फार्मासिस्ट रितु राणा, लैब टेक्नीशियन सेजल तथा पायलट शेखर ठाकुर का विशेष योगदान रहा।

संक्षिप्त खबरें

बजट 2026-27 पारित: विधानसभा की स्वीकृति से 58,830 करोड़ रुपये व्यय का मार्ग प्रशस्त

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को राज्य का वर्ष 2026–27 का बजट पारित कर दिया। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक–2026 प्रस्तुत किया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकृति मिल गई। इसके साथ ही राज्य सरकार को बजट में दर्शाई गई 5,88,30,66,70,000 रुपये की राशि वित्त वर्ष 2026–27 के दौरान व्यय करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

मुख्यमंत्री ने 21 मार्च को सदन में 54,928 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया था, जिसमें संचित निधि पर प्रभारित राशि शामिल नहीं थी। यह बजट वर्ष 2025–26 की तुलना में 3,586 करोड़ रुपये कम था।

पारित बजट के अनुसार वर्ष 2026–27 में प्रदेश की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 40,361 करोड़ रुपये तथा कुल राजस्व व्यय 46,938 करोड़ रुपये रहने का

आकलन है। इस आधार पर 6,577 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित है, जबकि राजकोषीय घाटा 9,698 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.94 प्रतिशत है।

बजट प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 100 रुपये के व्यय में से 27 रुपये वेतन, 21 रुपये पेंशन, 13 रुपये ब्याज अदायगी, 9 रुपये ऋण अदायगी, 10 रुपये स्वायत्त संस्थाओं को अनुदान तथा शेष 20 रुपये पूंजीगत कार्यों व अन्य गतिविधियों पर व्यय किए जाने का प्रावधान है।

एलपीजी एवं पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य, कालाबाजारी व जमाखोरी पर कड़ी निगरानी

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला शिमला नरेंदर धीमान ने आज यहां बताया कि जिला शिमला में वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत एलपीजी एवं पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर स्थिति सामान्य एवं नियंत्रित बनी हुई है।

यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न परिस्थितियों के कारण एलपीजी आपूर्ति पर कुछ प्रभाव पड़ा है, परन्तु जिला में घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है तथा पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूर्व की भांति नियमित रूप से की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को भी सुचारू किया गया है तथा अब व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति 50 प्रतिशत आरम्भ कर दी गई है। जिला के होटल, रेस्तरां एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पर्याप्त मात्रा में व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि वे घरेलू सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए न करें तथा ईंधन के वैकल्पिक साधनों का भी उपयोग करें।

ग्राम पंचायत बसोधन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण योजना के तहत जागरूकता अभियान कार्यक्रम

हामिद खान

चंबा। सोमवार को जिला चंबा के ग्राम पंचायत बसोधन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों एवं बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को विधिक सेवाएं योजना, 2024 के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, उनके लिए उपलब्ध कानूनी सहायता तथा सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना था।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रावधानों, नि:शुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता, तथा विभिन्न सरकारी सहायता योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम सहभागितापूर्ण रहा, जिसमें उपस्थित लोगों ने सक्रिय रूप से प्रश्न पूछे, जिनका संतोषजनक उत्तर दिया गया।

कार्यक्रम में सहायक विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता, नवीन सिंह ठाकुर द्वारा संबोधन किया गया। उनके साथ सुश्री मनीषा कुमारी (पी.एल.वी.) एवं श्री अब्दुल शेख (चपरासी, डीएलएसए चंबा) उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान किया।

इस अवसर पर सीएमओ कार्यालय से डॉ. प्रतीक ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया।

नगर पंचायत गगरेट में वार्ड आरक्षण का रोस्टर जारी

टीम एक्शन इंडिया

ऊना। नगर पंचायत गगरेट में आगामी चुनावों को लेकर वार्डों का आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जारी रोस्टर के अनुसार वार्ड नंबर 3, 4 और 7 को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि वार्ड नंबर 5 को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित किया गया है। रोस्टर लागू होने के बाद कई पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों की चुनावी रणनीति पर सीधा असर पड़ा है। खासतौर पर पूर्व प्रधान अनिल कुमार और सुरेंद्र सिंह के वार्डों को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने से उनके राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इन वार्डों से अब महिला उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतर सकेंगी, जिससे नए चेहरों को अवसर मिलने की संभावना बढ़ गई है।

सलोह में ज्वेलर्स की दुकान से 35 लाख के गहने चोरी

राजन पुरी

ऊना। जिला ऊना के हरोली उपमंडल के सलोह गांव में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने एक %वेलर्स की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के गहनों और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान के ताले और शटर तोड़कर अंदर घुसे और करीब 8 किलोग्राम चांदी, 100 ग्राम सोना तथा 80 हजार रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। गहनों की कीमत 35 लाख रुपये बताई जा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है, वहीं स्थानीय दुकानदारों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि

आरोपियों का सुराग लगाया जा सके। जानकारी के मुताबिक अजय कौशल निवासी कांगड़ पिछले लंबे समय से सलोह में %वेलर्स की दुकान करता है। रविवार को वह कुछ समय के लिए अपने ब%चों के साथ दुकान पर आए, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उन्होंने एहतियातन सीसीटीवी और अन्य बिजली उपकरण बंद कर दिए थे। अजय कौशल ने बताया कि सोमवार सुबह दुकान के मकान मालिक ने उन्हें ताले टूटे होने की सूचना दी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और पाया कि दुकान के अंदर सारा सामान विखरा पड़ा। अजय ने बताया कि चोर दुकान का शटर और ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए और गहनों सहित नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार दुकान से करीब 8 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना और 80 हजार रुपए की नकदी चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि शातिर करीब 35 लाख रुपये के गहने अपने साथ लेकर फरार हो गए।

हिमाचल प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा राज्यस्तरीय बैठक का किया आयोजन

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। हिमाचल प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा जिला हमीरपुर के पैराडाइज होटल में एक राज्यस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों—ऊना, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, शिमला आदि—से लगभग 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष शादी लाल गोस्वामी ने की। इस अवसर पर संघ के संरक्षक एस. के. पराशर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में जिला कांगड़ा के अध्यक्ष अमन गुलेरिया, महासचिव स्वर्ण सिंह सिंह राजपूत, कैशियर सुखपाल सिंह गोगी, जिला कांगड़ा से परमिंदर, जिला हमीरपुर के अध्यक्ष संदीप कुमार, महासचिव अरुण चौहान, जिला बिलासपुर के महासचिव मनुज चंदेल, कैशियर चंचल धीमान, जिला मंडी के अध्यक्ष दर्शन ठाकुर, जिला कुल्लू की महासचिव बनिता शर्मा, जिला शिमला के महासचिव सुभाष ठाकुर, राष्ट्रीय कोच जितेश्वर दत्ता, जिला ऊना के महासचिव ओंकार राणा तथा राज्य तलवारबाजी के उपाध्यक्ष अमित ठाकुर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

संतोषगढ़ में निर्माणाधीन उद्योग का एकता मंच ने खुलकर किया विरोध

राजन पुरी

ऊना। संतोषगढ़ में प्रस्तावित उद्योग का विरोध तूल पकड़ने लगा है। स्थानीय एकता मंच ने उद्योग का खुलकर विरोध करते हुए कहा कि उद्योग का निर्माणकार्य बिना एनओसी चल रहा है। यह आरोप एकता मंच के पदाधिकारियों ने स्थानीय गौशाला प्रांगण में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान लगाया। मंच के सदस्यों ने उद्योग से जुड़े अब तक के घटनाक्रम और विभिन्न स्तरों पर उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी।

एकता मंच के चेयरमैन शादी लाल शर्मा ने कहा कि उद्योग स्थापित करने वाली टीम के पास आवश्यक एनओसी तक नहीं है। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है, जो नियमों का उगंघन है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर संतोषगढ़ के लोग पूरी तरह एकजुट हैं और क्षेत्र के हितों के लिए यह एकता मंच आगे भी मजबूती से संघर्ष करता रहेगा।

बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं है मंजूर : उपायुक्त

चमन शर्मा

शिमला। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है, इसलिए ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए जो बिना किसी लेबल के बाजार में बिक रही हैं। उपायुक्त आज यहाँ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम आ रहा है और ऐसे में बाजार में कई ऐसी खाद्य वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं जिनकी गुणवत्ता की कोई जानकारी नहीं होती इसलिए यह जरूरी है कि ऐसे पदार्थों की बाजार में बिक्री न हो। ऐसे खाद्य पदार्थों की जांच अवशय करें जिनमें कृत्रिम रंग या स्वाद के लिए केमिकल का उपयोग किया जा रहा हो। उन्होंने विभाग को खाद्य वस्तुओं के सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बनने वाले खाने के भी सैंपल एकत्रित कर उनकी जाँच करे। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा मशोबरा, घणाहट्टी आदि क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों से मिड–डे मील के सैंपल लिए गए थे जिस पर उपायुक्त ने विभाग को जिला के दूर दराज के क्षेत्रों से भी सैंपल लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग को रोहड़ू, चिड़गांव, कुपवी, चौपाल जैसे दूर दराज क्षेत्रों से भी सैंपल लेने चाहिए और वहां की जनता को जागरूक करने के लिए जागरूकता कैंप आयोजित करने चाहिए।

गत बैठक में उपायुक्त ने स्कूल परिसरों के नजदीक चल रहे खाद्य विक्रेताओं की जांच और उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए थे जिस पर उन्हें अवगत करवाया गया कि गत बैठक से लेकर अभी तक 12 निगरानी नमूने लिए गए हैं और नगर निगम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थानों में लगभग 30 निरीक्षण किए गए हैं।

ऊना शहर के निजी अस्पताल से डॉक्टर की गाड़ी चोरी

राजन पुरी

ऊना। पुराना होशियारपुर रोड़ पर स्थित एक निजी अस्पताल से डॉक्टर की गाड़ी चोरी होने की घटना सामने आई है। चोर ने न केवल अस्पताल परिसर में घुसकर बेखौफ तरीके से तलाशी ली, बल्कि मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर की निजी गाड़ी के साथ–साथ जरूरी मशीनरी भी चुरा ली। हैरानी की बात यह है कि पूरी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें आरोपी की गतिविधियां साफ देखी जा सकती हैं।

वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और आरोपी तक पहुंचने के लिए तकनीकी साक्ष्यों के साथ–साथ सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। जानकारी के अनुसार चोरी की यह घटना रवि–सोम की रात्रि दो के बाद की बताई जा रही है। सुबह जब डॉक्टर जगदीश्वर कंवर रोजाना की तरह अस्पताल पहुंचे और राउंड लेने के बाद वापस लौटे तो, उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी पार्किंग से गायब है। शक होने पर उन्होंने अस्पताल परिसर की जांच की, जहां मुख्य गेट खुला मिला। इसके बाद तुरंत सीसीटीवी विशेषज्ञ को बुलाकर फुटेज खंगाली गई। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि एक अज्ञात व्यक्ति रात के समय अस्पताल में दाखिल होता है और बड़ी ही शांति से विभिन्न कमरों में जाकर तलाशी लेता है। इस दौरान वह फार्मेसी स्टोर तक पहुंचता है, जहां से उसे गाड़ी की चाबी मिल जाती है। इसके बाद वह नीचे जाकर अस्पताल में रखी एक मशीन उठाता है और फिर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो जाता है। डॉक्टर कंवर ने बताया कि उन्हें फास्टैग के माध्यम से प्राप्त संदेश के अनुसार उनकी गाड़ी सुबह करीब 6:15 बजे पंजाब के कुराली टोल प्लाजा को पार करती हुई दर्ज हुई है, जिससे अंदेशा है कि आरोपी रा%य से बाहर भाग चुका है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने अस्पताल परिसर से सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली है और फास्टैग से मिले इनपुट के आधार पर गाड़ी को ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई गाड़ी और मशीनरी बरामद कर ली जाएगी।